● वर्ष-5

● अंक-167

रायपुर, गुरुवार
26 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› कांग्रेस भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट ...

पीएम मोदी ने इस्राइली संसद को संबोधित किया

हमारी सभ्यता, हमारे त्यौहार एक हैं: मोदी

तेल अवीव। करीब नौ साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्राइल की राजकीय यात्रा पर हैं। हवाई अड्डे पर उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने इस्राइली संसद को संबोधित किया और ऐसा करने वाले वह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं।

संसद अध्यक्ष अमीर ओहाना ने पीएम मोदी के भाषण के लिए रखे गए विशेष सत्र में सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष इसहाक एमिट को आमंत्रित नहीं किया। इस फैसले के विरोध में विपक्षी सांसद सत्र की शुरुआत में ही सदन से बाहर चले गए। जब विपक्षी सांसद बाहर गए तो उनकी खाली सीटों पर सत्तापक्ष के पूर्व सांसद आकर बैठ गए। कई विपक्षी दलों ने बयान जारी कर कहा कि वे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के भाषण में शामिल नहीं होंगे और केवल तब सदन में लौटेंगे जब नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे।

नेसेट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे त्योहार भी एक-दूसरे से मेल खाते हैं। आप लोग हनुक्का मनाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। उसी समय पर हम लोग दिवाली मनाते हैं। भारत रंगों के साथ होली मनाता है। इसी दौरान इस्राइल पुरिम का त्योहार मनाता है।

एफटीए पर वार्ता के लिए कड़ी मेहनत कर रही हमारी टीमें

इस्राइली संसद में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अन्य देशों के साथ कई अहम व्यापार समझौते किए हैं। हमारी टीमें महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं।

नेसेट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, पिछले महीने दुनिया ने अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस (इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबरेंस डे) मनाया। होलोकास्ट मानवता के सबसे काले अध्यायों में से एक है। फिर भी उन

उथल-पुथल भरे वर्षों में भी मानवता के कुछ कार्य उल्लेखनीय थे। जाम साहब के नाम से मशहूर गुजरात के नवानगर के महाराजा ने पोलिश बच्चों को शरण दी, जिनमें यहूदी बच्चे भी शामिल थे, जिनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। उन्होंने कहा, यहूदी समुदाय भारत में उत्पीड़न या भेदभाव के डर के बिना रहते आए हैं। वे अपने धर्म का पालन करते हैं और समाज में पूरी तरह से भाग लेते हैं। यह उपलब्धि हमारे लिए गर्व का स्रोत है।

दोनों ही प्राचीन सभ्यताएं

इस्राइली संसद में पीएम मोदी ने कहा, भारत और इस्राइल दोनों ही प्राचीन सभ्यता हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमारे सभ्याताओं में कई समानताएं हैं। इस्राइली सभ्यता में तिकुल ओलाम का सिद्धांत है। भारत में यह वसुधैव कुटंबकम है। हमारे लिए दुनिया एक परिवार की तरह है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत की संसद ने इस्राइल के लिए एक संसदीय समूह बनाया है।

आयुर्वेद में रुचि बढ़ रही

प्रधानमंत्री मोदी ने इस्राइली संसद को संबोधित करते हुए कहा, जब मैं पहली बार 2006 में इस्राइल आया था, तब यहां चुनिंदा योग के केंद्र थे। आज यहां के हर पड़ोस में योग साधना की जा रही है। मुझे बताया गया है कि आयुर्वेद में भी इस्राइल की रुचि बढ़ रही है।

बस्तर उद्योगपतियों को सौंपने का दुष्प्रचार:साय

विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सदन में कहा कि यह आरोप लगाया जाता है कि बस्तर में नक्सलवाद इसलिए समाप्त किया जा रहा है ताकि उद्योगपतियों को बसाया जा सके। यह बात पूरी तरह दुष्प्रचार है। हम वहां कृषि करना चाहते हैं, सिंचाई का साधन बनाना चाहते हैं। वहां कई वॉटरफॉल है, पर्यटन बढ़ाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने कांग्रेस शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार के कचरे को साफ किया है। अक्सर कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के मामलों में छोटी मछलियां पकड़ ली जाती हैं और मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अब प्रदेश को लूटने वाले मगरमच्छ जेल की सलाखों के पीछे हैं, और जो अभी बाहर हैं, वे भी जल्द ही जेल के भीतर होंगे। इसके बाद विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धरमलाल कौशिक ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को असफल बताया है। जबकि गृहमंत्री विजय शर्मा ने प्रशासन के फेल होने के आरोपों को नकारा है।

चंद्राकर ने एम्स में सामाजिक न्याय मंत्रालय के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नशीले ड्रग यूजर डेढ़ लाख से 2 लाख हो गई है। जबकि गांजा पीने वाले संख्या 3.8 लाख से 4 लाख है।

इसी तरह 10 से 17 साल के 40 हजार से ज्यादा बच्चे और किशोर इन्हेलेंट्स और कफ सिरफ के शिकार हैं। नशे की लत की वजह से मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या कर रहे हैं। इसमें मृत्यु दर 250 से 300 है। चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन इसे रोकने में असफल रहा है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि साल 2026 में (31 जनवरी 2026 तक) कुल 146 प्रकरणों में 257 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2025 में 16 आरोपियों की करीब 13.29 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई है। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में टास्क फोर्स बनाई है। यह कहना गलत है कि प्रशासन फेल रहा है।

भूपेश बघेल ने कहा कि नशा और तस्करी पर ध्यानाकर्षण में चर्चा चल रही थी। तब ही विषय शराब पर भी आ गया। इस पर गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा -शराब पर चर्चा लंबी है फिर कर लेंगे, शराब पर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। गृहमंत्री विजय शर्मा की इस बात पर ही भूपेश बघेल ने तीखे तेवर में कहा -सत्र चल रहा है.. कितनी भी लंबी बात हो.. कितनी भी दूर जाएगी..जाने दीजिए.. और चर्चा कराइए।

इससे पहले प्रश्नकाल में अजय चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और रैपिडो जैसे प्लेटफॉर्म वर्करों की सुरक्षा और श्रम अधिकारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि गिग वर्करों को संगठित श्रमिक माना जाएगा या असंगठित, और तेज डिलीवरी के दबाव में उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने जवाब दिया कि फिलहाल गिग वर्करों को न तो संगठित और न ही असंगठित श्रमिक माना गया है। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियम भारत सरकार के अधिनियम के अनुसार लागू होंगे, और राज्य सरकार केंद्र द्वारा अधिसूचित नियमों का पालन करेगी।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि आज तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित हॉस्पिटल में मेरे कमर संबंधी (स्लिप डिस्क) समस्या का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। चिकित्सकों के परामर्श अनुरूप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहा हूं।

छत्तीसगढ़ के युवा नशे की चपेट में

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि मैक्सिको में ड्रग तस्कर एलमैंचो के एनकाउंटर के बाद वहां के 12 जिलों में हिंसा भड़क गई है। छत्तीसगढ़ के युवा नशा की चपेट में हैं। रायपुर में हर जगह आसानी से नशीले पदार्थ उपलब्ध है। पुलिस आरक्षक भी इस मामले में पकड़ा गया है।

इसे रोकने में प्रशासन विफल रहा है। कुछ दिनों पहले रायपुर में गांजे की पैकेजिंग करने वालों को पुलिस ने पकड़ा था और उनके पास ऐसे हाईटेक कैमरे थे, जिससे उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि पुलिस आने वाली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशीली पदार्थों जैसे चरस, गांजा, ब्राउन शुगर, हेरोइन, अफीम, डोडा, नशीली गोलियां की तस्करी पर लगाम लगाना अब असंभव सा हो गया है, अवैध तस्करी की घटनाऐं बढ़ती ही जा रही हैं।

गोंदिया-जबलपुर दोहरी रेल लाइन परियोजना को केंद्रीय स्वीकृति

रायपुर/बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेल मंत्रालय की गोंदिया-जबलपुर दोहरी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत - 5,236 करोड़ है तथा इसे 5 वर्षों की अवधि में पूर्ण किया जाएगा । गोंदिया-जबलपुर दोहरीकरण परियोजना गोंदिया पर हावड़ा-मुंबई उच्च घनत्व रेल मार्ग तथा जबलपुर पर इटारसी- वाराणसी उच्च उपयोगिता रेल मार्ग को जोड़ती है । यह प्रयागराज एवं वाराणसी से चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की ओर सबसे छोटा रेल मार्ग उपलब्ध

कराएगी, जिससे उत्तरङ्गदक्षिण रेल संपर्क को सुदृढ़ता मिलेगी ।

होने वाले प्रमुख लाभ: यात्री एवं मालगाड़ियों के संचालन में वृद्धि तथा रेल क्षमता में उल्लेखनीय विस्तार, प्रमुख तीर्थ स्थलों- अयोध्या धाम, वाराणसी, प्रयागराज, रामेश्वरम, मदुरै आदि-के लिए बेहतर एवं सुगम रेल संपर्क, प्रमुख पर्यटन स्थलों-कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच टाइगर रिज़र्व, कचनार शिव मंदिर, गांगुलपारा बाँध, धुआंधार जलप्रपात आदि-तक आसान आवागमन, विद्युत संयंत्रों, आयुध निर्माणी, खनन क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को बेहतर रेल सुविधा, अतिरिक्त माल परिवहन क्षमता 7.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष

प्रति वर्ष लगभग 16 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, जो लगभग 63 लाख वृक्षारोपण के समतुल्य है,परिवहन लागत में बचत- लगभग 350 करोड़ प्रतिवर्ष। लगभग 78 लाख मानव-दिवस, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत नियोजित यह परियोजना एकीकृत योजना एवं बहुआयामी संपर्क को सुदृढ़ करेगी ।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित बीटीआई मैदान में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह तीसरा वर्ष चल रहा है और दो वर्ष पूरे हो चुके हैं।

प्रमुख समाचार

राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली: गोयल

नईदिल्ली। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी के हमलों का जवाब देते हुए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को आरोप लगाया कि गांधी परिवार पूरी तरह से समझौतावादी राजनीतिक परिवार है और कांग्रेस एक समझौतावादी

राजनीतिक दल है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, गोयल ने पूर्व प्रधानमंत्रियों राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के कुछ फैसलों की भी आलोचना की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर प्रधानमंत्री समझौतावादी हैं के आरोपों के साथ सरकार पर हमला कर रहे हैं। गोयल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी का मतलब समझौता है। एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के शर्टलेस विरोध को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान के बीच, गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी नकारात्मक राजनीति के प्रतीक बन गए हैं।

मदरसों को बंद करो, इनमें पलते हैं आतंकी: नितेश राणे

मुंबई। महाराष्ट्र के बंदरगाह विकास मंत्री और भाजपा नेता नितेश राणे ने बुधवार को मदरसों को आतंकवादियों के लिए पनपने की जगह करार दिया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में इस्लामी स्कूलों को बंद करने का आग्रह करेंगे। विधानसभा भवन परिसर

में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने हमले को और तीखा बनाने के लिए एक वायरल वीडियो का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर एक मौलवी एक छात्र को पीटते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा, आपने बच्चों को पीटते हुए मौलवी का वीडियो देखा है। यह सावंतवाड़ी का है, जो मेरा गृह जिला है और मैं जिले का पालक मंत्री भी हूं। आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ क्या सख्त कार्रवाई होने वाली है। राणे सिद्धदुर्ग जिले के कंकावली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नितेश राणे ने कहा, मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अगली बार बच्चों के साथ ऐसा करने से पहले उनके हाथ कांप उठेंगे। भाजपा नेता ने मदरसों की जरूरत पर भी सवाल उठाया।

पार्टी अपने युवा निडर सिपाहियों के साथ खड़ी : प्रियंका

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस द्वारा इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा निडर सिपाहियों के साथ खड़ी है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पोस्ट

कर लिखा कि सत्य के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है जो हमें महात्मा गांधी और लाखों-करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली है। दुनिया भर के दबाव में झुककर, भारत के हितों से समझौता करने वाली केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। जनता की आवाज उठाने के लिए युवा कांग्रेस के साथियों पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय एवं शर्मनाक है। दरअसल यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिब की गिरफ्तारी पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जो लोग जनता के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो आम लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जो किसानों की आवाज उठा रहे हैं, केंद्र सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है।

राज्यपाल का अभिभाषण झूठे आंकड़ों का पुलिंदा: विजय

मुंबई महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने बुधवार को सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को पुरानी बातों का दोहराव और शब्दों का बाजार बताया। वडेट्टीवार ने

कहा कि यह भाषण पूरी तरह से निराशाजनक है। विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए वडेट्टीवार ने महायुति सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्यपाल को सदन के सामने खुला झूठ पेश करने के लिए मजबूर किया। यह महाराष्ट्र की जनता के साथ धोखा है। वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार राजनीतिक दिखावे के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, शाहू महाराज और डॉ. बी.आर. आंबेडकर का नाम लेती है। लेकिन अपने कामों से लगातार उनकी विचारधाराओं का अपमान करती है। इस सरकार ने उन लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, जिन्होंने राजभवन में बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया था। डॉ. आंबेडकर ने सभी को समानता से जीने का अधिकार दिया।

देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा में रनिंग ट्रायल सफल

जींद । देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का बुधवार को ट्रायल शुरू हुआ। ट्रेन का जींद रेलवे स्टेशन से ललितखेड़ा स्टेशन तक करीब 20 किलोमीटर तक सफल ट्रायल हुआ। इसके बाद डीजल इंजन लगाकर ट्रेन को मोहाना स्टेशन तक ले जाया गया। रेलवे अधिकारियों ने ट्रायल को संतोषजनक बताया है। हाइड्रोजन ट्रेन को बुधवार की सुबह 7 बजे यार्ड से बाहर निकाला गया। डीजल इंजन की सहायता से पहले ट्रेन को हांसी रोड पुल के नीचे लाया गया। यहां ट्रेन थोड़ी देर रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को वापस जंक्शन पर लाया गया। यहां से सुबह 8:25 बजे ट्रेन सोनीपत की ओर रवाना हुई।सुबह 8:40 बजे बजे डीजल इंजन की मदद से ट्रेन पिंडारा तक लाई गई। यहां से डीजल इंजन हटाकर ललितखेड़ा तक हाइड्रोजन इंजन से ट्रेन का रनिंग ट्रायल हुआ। दोनों स्टेशनों के बीच दो बार ट्रेन को चलाया गया। इस दौरान ट्रेन की स्पीड करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई। पिंडारा पहुंचने के बाद गोहाना से आगे मोहाना तक डीजल इंजन के साथ ही हाइड्रोजन ट्रेन को ले जाया गया। फिर मोहाना से वापस जींद की तरफ ट्रेन को लाया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान तकनीकी टीम ने बारीकी से निगरानी की।

भागवत जी के भाषण को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए

विश्वास डावर

सरसंघचालक (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख) श्री मोहन भागवत जी के भाषण को सही नजरिए से देखा जाना चाहिए-जिसमें उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अपना असली धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया था, उनका वापस स्वागत है-इस बात में कोई सांप्रदायिक भावना नहीं दिखनी चाहिए। जैसा कि इतिहास बहुत साफ है, भारत में सैंकड़ों सालों तक, मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं को अपना धर्म छोडने के लिए मजबूर किया। इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने के लिए, यूरोपीय शासकों ने उन पर मुकद्दमा चलाया और कई मामलों में, धर्म के आधार पर अमानवीय अत्याचार और बेरहमी से हत्याएं हुईं।

भारत में इस्लाम और ईसाई धर्म को जबरदस्ती और कई दूसरी चीजों से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद और सेवा की आड़ में फैलाया गया। भागवत जी की बात बहुत सीधी और सरल है-अगर कोई अपनी मर्जी से अपने असली धर्म में वापस आना चाहता है, तो हमें हिंदू समाज के तौर पर उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव और ऐसी शर्तों के तहत अपना असली धर्म छोड़ा जो उनके नियंत्रण से बाहर थीं। मुझे इसमें कोई गैर-धर्मनिरपेक्ष काम नहीं दिखता, क्योंकि इसमें दबाव, लालच या किसी भी गलत तरीके का कोई तत्व नहीं है। भारत जैसे आजाद और स्वतंत्र देश में, अपनी पसंद से धर्म बदलना गैर-कानूनी नहीं है। हिंदू धर्म (सनातन) सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं था, बल्कि इंडो-चाइना, इंडोनेशिया और दूसरे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों तक फैला हुआ था। इंडोनेशिया में ड्क्षहदू धर्म का काफी ज्यादा उभार हो रहा है, जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी है।

हिंदू-बहुल द्वीप बाली के अलावा, जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर हिंदू आबादी बढ़ रही है और नए हिंदू मंदिर बन रहे हैं। कुछ भी जबरदस्ती या किसी और गलत तरीके से नहीं हो रहा, यह सनातन धर्म की आध्यात्मिक आवाज है। इंसान की जिंदगी में शांति, खुशहाली और सुकून लाना ही सनातन धर्म कई यूरोपियन देशों जैसे पोलैंड, एस्टोनिया वगैरह में कर रहा है। हिंदू (सनातन धर्म) ने कभी किसी को धर्म

बदलने के लिए मजबूर नहीं किया। यह महान आध्यात्मिकता और फिलॉसफी की भावना है-सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबके लिए अच्छा सोचना और अपने आस-पास के सभी लोगों के साथ शांति से रहना। सनातन के इन बुनियादी सिद्धांतों ने इसे हजारों सालों तक सभी मुश्किलों और हमलों के बावजूद जिंदा रहने में मदद की है।

दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो धर्म के हिसाब से पूरी तरह बदल गए हैं और स्पेन इसका एक उदाहरण है। स्पेन 700 सालों तक मुस्लिम शासन के अधीन था और 8वीं सदी की शुरुआत (711 ए.डी.) से 15वीं सदी के आखिर (1478 ए.डी.) तक वहां मुस्लिम आबादी थी। इस दौरान, लगभग 800 सालों तक, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच लड़ाइयां लड़ी गईं, जिन्हें रिकोनक्विस्टा के नाम से जाना जाता है, जिसके नतीजे में स्पेन फिर से एक ईसाई देश बन गया। इतिहास साफ दिखाता है कि जहां भी इस्लामी राज कायम हुआ, पूरे देश मुस्लिम बन गए। इसी तरह, जहां यूरोपियन राज करते थे, वे ईसाई बन गए। हालांकि, भारत और सनातन धर्म अपनी पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे, भले ही दबाव में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए, जिनको बदला जा सकता है और लोगों को घर वापसी करनी चाहिए। यह बात कि सनातन हजार सालों तक उन सभी हमलों से बचा रहा, सनातन की सबसे बड़ी ताकत है। इसके उलट, भारत का सनातन धर्म बिना किसी हिंसा के बचा रहा और फला-फूला। यह जीने का एकमात्र तरीका है, जो हमारे देश को बिना किसी डर, गोलियों, गोले या अमानवीय कामों के आगे बढने और फलने-फूलने में मदद कर सकता है, जिससे आम लोगों को इंसानी दुख और तकलीफ होती है।

कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने भागवत जी के इस सुझाव की आलोचना की है कि ड्क्षहदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिएं, जिन्हें अच्छी परवरिश दी जा सके। इसे भी सही नजरिए से देखना चाहिए। कम बर्थ रेट की वजह से, देखिए कि जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और बैल्जियम जैसे यूरोपियन देशों में क्या हो रहा है, जहां की आबादी में युवाओं का प्रतिशत बहुत कम है। उन्हें दिक्कतें आने लगी हैं, कम युवा आबादी की वजह से आप्रवासियों से इन देशों में कानून-व्यवस्था की बड़ी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। जापान जैसे देशों में भी कम जन्म दर की वजह से बूढ़ी होती आबादी की दिक्कतें देखी गई हैं। भारत में, ज्यादातर ड्क्षहदुओं की आबादी में कम जन्म दर डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए, जन्म दर पर उनके सुझावों को किसी खास समूह के लोगों के खिलाफ नहीं समझना चाहिए।

कांकेर में माओवादी मल्लेश ने एके-47 के साथ किया आत्मसमर्पण

कांकेर। नक्सलवाद की खोखली विचारधारा से त्रस्त होकर अब नक्सली संगठन कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल के दिनों में कई बड़े नक्सली नेताओं ने या तो आत्मसमर्पण किया है या पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए हैं। इसी क्रम में, तेलंगाना में 5 करोड़ के इनामी नक्सली ने अपने 16 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया है। वहीं, मंगलवार को कांकेर जिले के पखांजूर छोटेबेठिया में स्थित बीएसएफ 94वीं बटालियन में डीवीसीएम मल्लेश ने एके-47 राइफल के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। मल्लेश कई नक्सली घटनाओं में वांछित था और उसकी तलाश लंबे समय से जारी थी। जानकारी के अनुसार, डीवीसीएम रैंक का सक्रिय माओवादी मल्लेश कांकेर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के समक्ष उपस्थित हुआ और आत्मसमर्पण किया। बताया जा रहा है कि, वह लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। कोई लीडन न होने के चलते नक्सल संगठन को मल्लेश के आत्मसमर्पण से एक बड़ा झटका लगा है। इससे यह साबित होता है कि अब नक्सली विचारधारा ने अपना प्रभाव खो दिया है और नक्सली मुख्यधारा में लौटकर सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। इस तरह के आत्मसमर्पण नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत को दर्शाते हैं।

बस्तर के धुड़मारास में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ का स्वागत, पारंपरिक नृत्य-गीतों से हुआ अभिनंदन

बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और हिवा कोचिंग एंड कंसल्टिंग की संस्थापक किर्सी ह्यवैरिनेन के छह दिवसीय प्रवास का दूसरा दिन बस्तर की अनूठी परंपराओं और आत्मीय आतिथ्य के नाम रहा।

किर्सी ग्राम धुड़मारास की सुंदर वादियों में पहुंची, जहां धुरवा डेरा होमस्टे में उनका स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं था। धुड़मारास की धरती पर कदम रखते ही किर्सी का अभिनंदन स्थानीय परंपरा के अनुसार सिहाड़ी और महुए की विशेष माला पहनाकर किया गया। इस दौरान बस्तर की लोक संस्कृति की जीवंत झलक तब देखने को मिली, जब स्थानीय ग्रामीणों ने धुरवा नृत्य की थाप और पारंपरिक स्वागत गीतों के साथ उनकी अगवानी की। आत्मीयता के साथ किए गए इस स्वागत से किर्सी अभिभूत नजर आईं और कहा कि उन्हें अपने जीवन में इस तरह की अनुभूति पहली बार हो रही है।

स्वागत के पश्चात किर्सी ने बस्तर के पारंपरिक खान-पान का लुत्फ उठाया, जहां दोपहर के भोजन में उन्हें पूरी तरह स्थानीय और जैविक व्यंजनों से सजी थाली परोसी गई। किर्सी का यह प्रवास मुख्य रूप से धुड़मारास और उसके आसपास के क्षेत्रों को विश्व स्तरीय पर्यटन मानकों के अनुरूप ढालने पर केंद्रित है। वे न केवल स्थानीय जीवनशैली का प्रत्यक्ष अनुभव ले रही हैं, बल्कि ग्रामीणों और हितधारकों के साथ सीधा संवाद कर पर्यटन के नए अवसरों की पहचान भी कर रही हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष ने फोस्टर केयर की जमीनी हकीकत जानी

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने हाल ही में जगदलपुर के प्रवास के दौरान फोस्टर केयर व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया और वहां निवासरत बच्चों से मुलाकात की। यह कदम बच्चों के कल्याण और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। फोस्टर केयर एक ऐसी व्यवस्था है जहां ऐसे बच्चे, जो किन्हीं कारणों से अपने माता-पिता के साथ नहीं रह पाते, उन्हें कुछ समय के लिए एक वैकल्पिक परिवार के सुरक्षित वातावरण में रखा जाता है। इस दौरान उनकी देखभाल, शिक्षा और समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। जगदलपुर के दूरस्थ गांवों, जैसे बाबूसेमरा और कलचा, में स्थित फोस्टर परिवारों से भेंट कर अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने बच्चों के हालचाल जाने और उनसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद व उनकी व्यक्तिगत रुचियों जैसे विभिन्न विषयों पर संवाद किया।

निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि फोस्टर केयर का क्रियान्वयन संतोषजनक स्तर पर हो रहा है। विशेष रूप से, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के एक ही परिवार के तीन बालकों ने, जो वर्तमान में फोस्टर केयर में रह रहे हैं, भविष्य में भारतीय सेना में सेवा देने की इच्छा व्यक्त की है। यह उनकी मजबूत इच्छाशक्ति और सकारात्मक सोच का प्रतीक है।

एक अन्य मामले में, एक बालिका जो पहले दुर्ग बालिका गृह और राजनांदगांव में फोस्टर देखरेख में रह चुकी है, अब कलचा के एक परिवार के साथ निवासरत है। पिछले एक वर्ष से वह इस परिवार में पूरी तरह से घुलमिल गई है। उसने स्थानीय भाषा भतरी और हलबी भी सीख ली है और उसे संस्कृत विषय में विशेष रुचि है।

विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका

चुनावी याचिका खारिज कराने की एसएलपी रद्द

दुर्ग। दुर्ग जिले के भिलाई नगर विधानसभा से विधायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव को सर्वोच्च न्यायालय से करारा झटका लगा है। भाजपा नेता और देवेंद्र यादव के खिलाफ विधानसभा में प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडे के द्वारा हाईकोर्ट में लगाए गए चुनाव याचिका के खिलाफ देवेंद्र यादव सुप्रीम कोर्ट गये थे। सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र यादव ने एसएलपी दाखिल की थी। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निराधार मानकर खारिज कर दी। इसे विधायक देवेंद्र यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

भिलाई नगर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने 2018 और 2023 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे को करारी शिकस्त दी थी। भाजपा के प्रत्याशी रहे प्रेम प्रकाश पांडे ने चुनाव में गलत हलफनामा देने का आधार बता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी और उनका निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। प्रेम प्रकाश पांडे की याचिका के अनुसार 2018 और 2023 के चुनावों में दिए गए शपथ पत्र में संपत्ति का मूल्य देवेंद्र यादव ने गलत दर्शाया था। इसके अलावा चुनाव शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरणों की जानकारी छुपाते हुए घोषित फरार आरोपी होने की जानकारी नहीं दी थी। यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। इतना ही नहीं चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जो भ्रष्ट आचरण माना जाता है, जिसके तहत भाजपा के प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर देवेंद्र यादव का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की थी। देवेंद्र यादव ने हाईकोर्ट में लगी याचिका के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) लगा हस्तक्षेप करने की मांग की थी। पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद विशेष अनुमति याचिका को निराधार मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया और देवेंद्र यादव की याचिका खारिज कर दी।

खेत में चल रहे सागौन लकड़ियों के अवैध चिरान पर वन विभाग की दबिश

- 18 लट्ठे के साथ 2 मजदूर पकड़ाए, मुख्य सरगना फरार

गरियाबंद। देवभोग नगर से लगे एक खेत में सागौन लकड़ियों के अवैध चिरान का बड़ा मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने दबिश देकर मौके से 18 नग सागौन लठ्ठा, 2 नग चिरान और 2 आरा जब्त किए हैं। साथ ही लकड़ी काटने में लगे दो मजदूरों को हिरासत में लिया गया है। बिना अनुमति के पिछले एक साल में राजस्व भूमि पर मौजूद 150 से अधिक सागौन पेड़ कटवाकर बेचने वाला मुख्य सरगना मौके से फरार हो गया।

दरअसल, नगर के राजापारा तालाब से महज 1 कीमी दूरी पर मौजूद एक खेत में सागौन पेड़ का अवैध चिरान बना कर बेचने का खेल लंबे समय से चल रहा था। अवैध कारोबार की भनक लगते ही आज देवभोग रेंजर अश्वनी कुमार मुरचुलिया के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दिया। जहां दो मजदूर को सागौन लठ्ठा का चिरान बनाते रंगे हाथ पकड़ा। मौके पर एक आरोपी बैल जोड़ी से लठ्ठा लाते भी दिखा, लेकिन मौका देखकर फरार हो गया। टिम में शामिल डिप्टी रेंजर फिरोज खान,फॉरेस्ट गार्ड लम्बोदर सोरी,केशरी नायक ने सहयोगियों के साथ मिल कार्यवाही शुरू किया। कटिंग करते मिले मजदूर खरत राम,अंगद राम दोनों निवासी पूरनापानी ने लिखित बयान में बताया कि वे देवभोग निवासी बलभद्र नागेश के लिए लंबे समय से काम करते है,उन्हें रोजाना मजदूरी दिया करता था। जिसके बाद फॉरेस्ट की टिम ने मुख्य आरोपी बलभद्र के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत पीओआर दर्ज की कार्रवाई किया है।

टिम ने दिन भर में 4 मर्तबा आरोपी के घर में दबिश दिया, जो नदारद मिला। रेंजर अश्वनी कुमार मुर्चुलिया ने बताया कि 0.708 घन मीटर के 18 नग लठ्ठा और 0.024 घन मीटर के 2 नग चिरान समेत आरा जब्त किया गया है। जब्त इमारती की सरकारी कीमत 40526 आकी गई है। जल्द ही मुख्य आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। खेतों के आसपास कटे पेड़ों के ठूठ की गिनती कर भू स्वामी को भी नोटिस जारी कर, काटे गए पेड़ के लिए अनुमति की जानकारी ली जाएगी। नियम विरुद्ध पाया गया तो आवश्यक कार्रवाई होगी। बलभद्र अपने रिश्तेदार के जिस खेत में अवैध कटाई कर चिरान बनाता था उस खेत के आस पास 200 मीटर की परिधि में सागौन के सैकड़ों ठूंठ नजर आए।एक साल में 150 से ज्यादा सागौन पेड़ तो 5 साल में 1500 इमारती की अवैध कटाई का अनुमान है। कटिंग के लगे मजदूरों ने बताया कि एक पेड़ को बलभद्र 5 से 10 हजार में खरीदी करता है फिर उसे चौखट और चिरान बना कर देवभोग और आसपास के लोगों को उपलब्ध कराता है।प्रति चिरान1 हजार रुपये रो चौखट का एक सेट 2500 तक बेचे जा रहे। एक पेड़ में अधिकत 30 हजार की कमाई कर लेता है।

निजी अथवा राजस्व भूमि में इमारती पेड़ काटने के लिए एसडीएम के पास निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन करना होता है। पेड़ काटने लायक है या नहीं इसका सत्यापन रिपोर्ट वन विभाग बना कर देता है। विभाजन शर्त और निर्धारित शुल्क जमा के बाद ही मालिक मकबूजा प्रकरण दर्ज कर पेड़ काटने की विधिवत अनुमति दी जाती है। लेकिन देवभोग से लगे इस इलाके में सागौन पेड़ों की कटाई धड़ल्ले से नियम विरुद्ध किया जा रहा है। मुख्य सरगना अपने पहुंच का धौंस दिखाकर अपने रिश्तेदारों से खड़े पेड़ का सौदा कर अवैध कटाई को सालों से अंजाम देते आ रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

राजस्व वसूली में सीएमओ फेल राज्य सरकार ने किया निलंबित

कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन ने नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) अभिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक संपत्तियों के नए कर (मांग) निर्धारण का कार्य नहीं किया गया। शासन ने इसे कर्तव्यों के प्रति उदासीनता मानते हुए गंभीर कदाचार की श्रेणी में रखा है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। इसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम, 2017 के नियम-33 के अंतर्गत अभिताभ शर्मा को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान शर्मा का मुख्यालय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है।

शिकायत निवारण का माध्यम बनेगी नारी अदालत

बैकुण्ठपुर। कलेक्टर चंदन त्रिपाठी के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत सलका में नारी अदालत का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायत मनसुख एवं ग्राम पंचायत सलका में गठित नारी अदालत के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया। नारी अदालत मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं से संबंधित शोषण, घरेलू हिंसा, अधिकारों में कटौती एवं अन्य सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करेगी। नारी अदालत महिलाओं का एक सशक्त समूह है जिसमें समाज एवं शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय महिलाएं शामिल हैं। यह समूह विभिन्न प्रकार के विवादों के समाधान, परामर्श, साक्ष्यों के आधार पर निर्णय, आपसी सहमति से मध्यस्थता एवं सुलह तथा महिलाओं के अधिकारों एवं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य करेगा।

पीड़ित के लिए प्रत्येक थाना - चौकी में दो कुर्सियां आरक्षित

कोरिया। जिला कोरिया पुलिस द्वारा जन-संवेदनशील पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हुए एक महत्वपूर्ण पहल की है। एसपी श्री कुर्रे के निर्देशन में जिले के समस्त थाना एवं चौकियों में पीड़ितों एवं सूचनाकर्ताओं के लिए दो-दो कुर्सियां आरक्षित कर उपलब्ध कराई हैं। एसपी ने निर्देशित किया कि थाना/चौकी में आने वाले प्रत्येक पीड़ित, फरियादी अथवा सूचना देने वाले नागरिक को सम्मानपूर्वक बैठाकर उनकी समस्या सुनी जाए। इसी उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सभी थाना एवं चौकी उपरोक्त सामग्री को उपलब्ध कराया गया है, जिसके फलस्वरूप जिले के समस्त थाना एवं पुलिस चौकियों में उक्त व्यवस्था कर ली गई है। इस पहल का उद्देश्य पुलिस एवं आमजन के मध्य विश्वास को सुदृढ़ करना तथा पीड़ितों के साथ संवेदनशील एवं गरिमामय व्यवहार सुनिश्चित करना है। जिला पुलिस यह मानती है कि प्रत्येक नागरिक सम्मान का अधिकारी है और उसकी समस्या को गंभीरता एवं सहानुभूति के साथ सुनना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी से ठगी, आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। कोतवाली पुलिस ने जाली पॉवर ऑफ अटॉर्नी से भूमि, दो लाख रूपए की ठगी किए जाने के आरोप में राजेश कुमार पांडेय को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से फर्जी मुख्तारनामाआम जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि शहर के चर्च रोड केदारपुर निवासी प्रीतपाल सिंह के द्वारा कोतवाली में यह शिकायत दर्ज कराई थी आरोपी ने शहर से लगे ग्राम मोरभंज लटोरी में मिना व देवमति की भूमि को 35 लाख रूपए में बेचने का सौदा किया था। जिससे प्रीतपाल ने अग्रिम राशि के रूप में चेक से दो लाख रूपए दिया था, मगर जांच में पता चला कि आरोपी राजेश कुमार पांडेय के पास असली पॉवर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। उसने जाली दस्तावेज दिखा कर ठगी की और धोखाधड़ी उजागर होने पर जब रूपए वापस मांगा गया तब टालमटोल किया जाने लगा। पुलिस ने बताया कि भूमि की मूल स्वामिनी देवमति से आरोपी ने छह मार्च 2023 को जरनल पॉवर ऑफ अटॉर्नी दो वर्ष के लिए लिया गया है। प्रथम दृष्टिया दोखाधड़ी सामने आने पर धारा 466, 468, 471 के तहत अपराध दर्ज किया गया।

बिना अनुमति निर्माण, निगम ने 5 दुकानों पर जड़ा ताला

बिलासपुर। शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइंस कॉलेज सीपत रोड क्षेत्र में बिना अनुमति बनाए जा रहे 5 दुकानों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों के मुताबिक संबंधित निर्माणकर्ता शहनवाज बटलर को पहले ही नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन समय सीमा के भीतर कोई वैध अनुमति या स्वीकृति प्रस्तुत नहीं की गई। इसके बाद निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकानों को सील कर दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि 3 और 17 फरवरी को नोटिस जारी कर निर्माण से संबंधित नक्शा, अनुमति पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे गए थे। नोटिस के बावजूद जवाब नहीं मिलने पर यह कार्रवाई की गई। निगम का कहना है कि संबंधित निर्माण बिना भवन अनुज्ञा के किया जा रहा था, जो नियमों के विपरीत है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया शहर में अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर निर्माण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

लीज अवधि खत्म होने के बाद रेलवे को जमीन अधिग्रहण का है अधिकार

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रेलवे भूमि से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिना वैध और नवीनीकृत लीज के रेलवे जमीन पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत ने इस आधार पर दीपचंद कछवाहा द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया। अपीलकर्ता दीपचंद कछवाहा, जो बिलासपुर रेलवे स्टेशन क्षेत्र स्थित अनंता होटल परिसर में व्यवसाय कर रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों द्वारा की जा रही बेदखली कार्रवाई को चुनौती दी थी। इससे पूर्व उनकी याचिका को 15 जनवरी 2026 को एकल पीठ द्वारा निस्तारित कर दिया गया था, जिसके विरुद्ध यह रिट अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा, वहीं रेलवे की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल उपस्थित हुए। दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि इसी प्रकार का मामला पहले ही असलम हुसैन बनाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में निस्तारित किया जा चुका है। अपीलकर्ता के पक्ष में कोई वैध, पंजीकृत और प्रभावी लीज मौजूद नहीं है। केवल लीज किराया या टैक्स जमा करने से कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता। लीज समाप्त होने और नवीनीकरण न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति अनधिकृत कब्जेदार माना जाएगा। रेलवे भूमि का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास है, और रेलवे पर अवैध कब्जे हटाने का वैधानिक दायित्व है। रेलवे के वाणिज्यिक विभाग में पुनर्वास या वैकल्पिक दुकान देने की कोई नीति अस्तित्व में नहीं है। रेलवे स्टेशन के विस्तार एवं परिचालन आवश्यकताओं के लिए भूमि की आवश्यकता होने पर रेलवे को लीज न बढ़ाने का अधिकार है। लंबे समय से कब्जे में रहना स्वामित्व या स्थायी अधिकार प्रदान नहीं करता। अदालत ने माना कि वर्तमान मामला पूरी तरह से डब्ल्यू ए 131 ऑफ 2026 के समान है, जिसमें पहले ही स्पष्ट कर दिया गया।

जलकर वसूली टीम से शख्स ने किया अभद्र व्यवहार

- गोली मारने की दी धमकी, निगम कमिश्नर ने एफआईआर के लिए स्वकको लिखा पत्र, पुलिस ने शुरू की जांच

जगदलपुर। नगर निगम की जलकर टैक्स वसूली टीम को जान से मारने की धमकी दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। बकाया जलकर की वसूली के लिए पहुंचे निगम कर्मचारियों के साथ एक व्यक्ति ने न सिर्फ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि गोली मारने की धमकी तक दे डाली।

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम धमकी देता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक, नगर निगम की टीम नियमित अभियान के तहत बकाया जलकर की वसूली के लिए संबंधित क्षेत्र में पहुंची थी। इसी दौरान एक व्यक्ति ने आपा खो दिया और कर्मचारियों से तीखी बहस शुरू कर दी। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने जगदलपुर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ तत्काल अपराध दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, आरोपी का गन लाइसेंस रद्द करने के लिए भी संबंधित विभाग को पत्र भेजा गया है, ताकि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका को रोका जा सके।

निगम कर्मचारियों का कहना है कि इस तरह की धमकियों से न सिर्फ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि वसूली अभियान के दौरान कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह खुलेआम जान से मारने की धमकी देना बेहद चिंताजनक है।

संक्षिप्त समाचार

शारदा चौक सड़क के चौड़ीकरण में विलंब का मुख्य कारण बाधारहित जमीन

रायपुर। रायपुर के तात्यापारा से शारदा चौक

सड़क का चौड़ीकरण का मामला रायपुर दक्षिण के विधायक सुनील कुमार सोनी ने उठाया। जिस पर उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण अरूण साव ने सदन को बताया कि राजधानी रायपुर के तात्यापारा से शारदा चौक सड़क के चौड़ीकरण की कार्य योजना प्रारंभ होने में विलम्ब का मुख्य कारण बाधारहित जमीन की अनुपलब्धता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक 19.07.2024 के अनुसार कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में कमेंटी गठन हेतु आदेशित है। कलेक्टर रायपुर की अध्यक्षता में बैठक 23.07.2024 में लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, नगर पालिका निगम रायपुर, रायपुर विकास प्राधिकरण, नगर तथा ग्राम निवेश रायपुर, पुलिस विभाग, जिला पंजीयक, जिला कोषालय (वित्त विभाग) को शामिल किया गया है। बाधारहित भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही निर्माण कार्य हेतु प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी।

अरुण साव ने केमिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण प्रदान किये

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार

को नवा रायपुर स्थित विधानसभा भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह सफलता उनके परिश्रम और लगन का परिणाम है। श्री साव ने चयनित अभ्यर्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए सभी को अपने दायित्वों का निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण भाव से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया, जिससे वे जनसेवा के माध्यम से जनस्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

नपं माना कैम्प में पीएम आवास योजना के तहत आवासों की स्वीकृति हैं निरंक

रायपुर। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल

साहू ने नगर पंचायत माना कैम्प में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान स्वीकृत हुये हैं या निर्मित हुये हैं? यदि नहीं हुये हैं तो क्यों? का मामला उठाया। उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरूण साव ने सदन को बताया कि पात्र हितग्राहियों को आवास का लाभ दिये जाने हेतु 1 सितम्बर 2024 से राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 लागू है। वर्तमान में योजनांतर्गत नगर पंचायत माना कैम्प में आवासों की स्वीकृति निरंक है। योजनांतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित नगरीय निकायों से जिला स्तरीय मूल्यांकन एवं निगरानी समिति से अनुशंसित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति के माध्यम से प्रस्ताव भारत सरकार की केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आवासों की स्वीकृति संबंधित नगरीय निकायों को प्रदान की जाती है। नगर पंचायत माना कैम्प से योजनांतर्गत आवासों की स्वीकृति हेतु उक्तानुसार प्रस्ताव प्राप्त नही होने के कारण नगरीय निकाय में योजनांतर्गत आवासों की स्वीकृति निरंक है।

मराठी भाषा दिवस पर 27 को छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में संगोष्ठी

रायपुर। महाराष्ट्र मंडल में मराठी अभिजात भाषा का कितना महत्व है, यह तो उस समय भी सिद्ध हो गया, जब पुणे से आए महानाट्य जाणता राजा के प्रबंधक डॉ. अजीत आप्टे ने कहा कि मंडल की ओर से पद्मजा लाड प्रतिदिन मराठी सिखाने के लिए ऑनलाइन क्लास लेती हैं। वास्तव में यह कौतुकास्पद है। असल में यह चर्चा शुक्रवार, 27 फरवरी को मंडल के छत्रपति शिवाजी महाराज सभागृह में आयोजित होने वाले मराठी अभिजात भाषा दिवस के मौके पर की जा रही है। साहित्य समिति प्रभारी कुमुद लाड ने बताया कि शुक्रवार शाम 6:30 बजे मराठी भाषा दिवस के अवसर पर मराठी अभिजात भाषा और हमारा समाज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसमें मराठी के जाने- माने वक्ता तो होंगे ही, साथ ही ऐसे भी गैर महाराष्ट्रियन अतिथि वक्ता होंगे, जो महाराष्ट्र में रहकर धाराप्रवाह मराठी बोलते हैं और कार्यक्रम में भी मराठी में संबोधित करेंगे। कुमुद लाड के साथ मंडल के अध्यक्ष अजय मधुकर काले ने अधिकाधिक श्रोताओं से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है।

व्यापार एवं उद्योग के लिए छत्तीसगढ़ में बना है अनुकूल माहौल : मुख्यमंत्री

सीएम साय कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में हुए शामिल

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर स्थित बीटीआई मैदान में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) द्वारा आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग के लिए भी अनुकूल वातावरण बना है, जिसका परिणाम है कि व्यापारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि राज्य में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वित्त मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह तीसरा वर्ष चल रहा है और दो वर्ष पूरे हो चुके हैं। पहले वर्ष प्रस्तुत बजट का थीम ज्ञान था, जिसमें जी का अर्थ गरीब, वाय का अर्थ युवा, ए का अर्थ अन्नदाता किसान और एन का अर्थ नारी था तथा इन सभी वर्गों के विकास पर विशेष फोकस किया गया था। दूसरे वर्ष उसी विकास को गति देने के उद्देश्य से बजट का थीम गति रखा गया, जबकि इस वर्ष का

बजट थीम संकल्प है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को आत्मसात करते हुए तैयार किया गया है और पूरे प्रदेश के हित में है। उन्होंने बताया कि इस बजट में विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा क्षेत्र पर किया गया है। उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र केरल राज्य से भी बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर है, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जा सकता है, लेकिन चार दशक से अधिक समय तक नक्सलवाद के कारण यह क्षेत्र विकास से अछूता रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व तथा हमारे वीर जवानों के अदम्य साहस के कारण नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का संकल्प लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में नक्सली सक्रिय थे, लेकिन विगत दो वर्षों में हमारे जवानों ने जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है, उसमें कई बड़े माओवादी मारे गए हैं तथा बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे राज्य अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि माओवाद के कारण इन क्षेत्रों में समुचित विकास नहीं हो पाया था, जिसकी भरपाई के लिए अब सरकार इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि सरकार ने अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी के लिए बजट में प्रावधान किया है। साथ ही क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने और फॉरेस्ट प्रोड्यूस के वैल्यू एडिशन पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा दोनों संभागों में सैकड़ों प्रकार के वन उत्पाद उपलब्ध हैं, जिनका मूल्य संवर्धन कर स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बजट पूरे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है और प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत 7 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं तथा उद्योग नीति के तहत काटे जाने वाले पेड़ों की भरपाई भी बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और उसी के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार ने विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान जीएसडीपी दर को आने वाले पांच वर्षों में दोगुना करने तथा वर्ष 2047 तक राज्य का जीएसडीपी 75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। नई उद्योग नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और विभिन्न बड़े शहरों में आयोजित इन्वेस्ट मीट के माध्यम से अब तक प्रदेश को लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर धरातल पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े निवेश भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में व्यापारी बंधुओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने नेशनल ट्रेड एक्सपो के सफल आयोजन के लिए कैट की पूरी टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ट्रेड एक्सपो में विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया तथा कैट द्वारा प्रकाशित स्वदेशी पोस्टर का विमोचन भी किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील सिंघी, रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर परवानी सहित कैट छत्तीसगढ़ के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विधानसभा बजट सत्र: भाजपा विधायकों ने उठाया नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा

■ प्रशासन को बताया फेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन ध्यानाकर्षण में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और धरम लाल कौशिक ने नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को असफल बताया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रशासन के फेल होने के आरोपों को नकारा।

भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नशे से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के आरक्षक ही नशा की बिक्री कर रहा है'। इसके कारण अपराध भी बढ़ रहा है, नशे की आगोश में है। इसे रोकने में प्रशासन विफल रहा है।

गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह आरोप सही नही है कि प्रशासन फेल है। विभाग संकल्पित है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी बदमाश या अपराधी ऐसी कृत्य कर रहे है, उनपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

टिकरापारा में आरक्षक पर कार्रवाई हुई, अभी प्रक्रियाधीन है।

अजय चंद्राकर ने कहा कि जब विपक्ष में था, तब भी सवाल उठाता था आज स्थिति उससे भी भयावह है। विजय शर्मा ने कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, सभी पर कार्रवाई होंगी। स्ट्रैटजी बदली गई है, अब एंड टू एंड कार्रवाई हो रही है।

विधायक सुशांत शुक्ला ने अवैध शराब को लेकर जानकारी मांगी। इस पर मंत्री ने कहा कि कई मामलों पर पुलिस सीधे कार्रवाई नहीं कर सकती है। पूरी कार्रवाई को लेकर विस्तृत जानकारी है। बैठक की जा रही है, मेडिकल दुकानों को भी हिदायत दी गई है। जिसके बाद उस पर भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।

विजय शर्मा ने कहा कि 24 घंटे आपके साथ खड़ा हूं, जानकारी पर कार्रवाई होगी। इस पर विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि- क्षेत्र में स्कूलों के पास नशे का व्यापार चल रहा है। अटल श्रीवास्तव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नशे के आदी आरोपी के परिजन की संपति राजसात हो रही है।

इस पर मंत्री ने कहा कि शराब पर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भूपेश बघेल बोले- दूर तक जाए तो जाने दीजिए, चर्चा कराइए। विजय शर्मा ने कहा कि नशे व्यापार करने वाला आरोपी और नशे का आदी व्यक्ति बेचारा होता है। राजेश मूणत ने कहा कि राजधानी में सूखा नशा बिक रहा है, उसको पकड़वाने वाले के लिए इनाम की घोषणा करें।

अनिला भेंडिया ने एसआईआर कार्य में शिक्षकों के संलग्न के कारण अध्ययन बाधित होने का मामला उठाया

■ प्रदेश में 18198 शिक्षक एसआईआर में कर रहे है कार्य, 91 शिक्षकों की विभिन्न शासकीय कार्यों में लगाई गई ड्यूटी

रायपुर। पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री व विधायक श्रीमती अनिला भेंडिया ने एसआईआर कार्य में शिक्षकों के संलग्न के कारण अध्ययन बाधित होने का मामला उठाया। जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने बताया कि प्रदेश में 18198 शिक्षक एसआईआर में कर कार्य कर रहे है और 91 शिक्षकों की विभिन्न शासकीय कार्यों में ड्यूटी लगाई गई है।

अनिला भेंडिया ने मंत्री से जानना चाहा कि एसआईआर के अलावा कितने कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाई गई है और क्यों? कृपया स्पष्ट करेंगे? स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि एसआईआर के अलावा 91 शिक्षकों की विभिन्न शासकीय कार्यों में स्थानीय एवं प्रशासकीय आवश्यकता के आधार पर ड्यूटी लगाई गई है। भेडिया ने फिर पूछा कि एसआईआर में संलग्न शिक्षकों के एवज में अध्यापन कार्य हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की गई है? क्या यह सत्य है कि एसआईआर कार्य में शिक्षकों के संलग्न होने के कारण अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ ? प्रदेश में कितने शिक्षक एसआईआर में संलग्न हैं? मंत्री यादव

ने बताया कि एसआईआर कार्य में संलग्न सभी शिक्षक अपने पदस्थ संस्था में रहकर ही कार्य कर रहे हैं तथा इन विद्यालयों में उपलब्ध अन्य शिक्षक संकुल स्तर के शिक्षकों से संबंधित कक्षाओं का अध्यापन कार्य कराया जा रहा है। जी नहीं। प्रदेश में 18198 शिक्षक एसआईआर में कार्य कर रहे हैं।

विधायक भेडिया ने मंत्री से सवाल किया कि विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं? गैर शिक्षकीय कार्यों से क्या गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो गुणवत्ता सुधार के लिए विभाग द्वारा क्या जिम्मेदारी तय की गई है? स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान (2025-26) के तहत नए मापदंड और रणनीतियाँ तय की गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्था को आधुनिक और परिणाम-आधारित बनाना है।

छत्तीसगढ़ में रिक्त दो राज्यसभा सीटों के लिए अधिसूचना आज

रायपुर। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा की कुल 05 सीटों में से 02 सीटें आगामी 09 अप्रैल 2026 को रिक्त होने जा रही हैं। राज्यसभा सदस्य श्री कवि तेजपाल सिंह तुलसी एवं श्रीमती फूलो देवी नेताम का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण इन पदों पर निर्वाचन कराया जाएगा। रिक्त होने वाली इन सीटों के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 18 फरवरी को प्रेस नोट जारी कर राज्यसभा द्विवार्षिक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 26 फरवरी को जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 05 मार्च निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की संवीक्षा 06 मार्च को की जाएगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार अभ्यर्थी 09 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 16 मार्च सोमवार को प्रातः 09 बजे से सायं 04 बजे तक होगा। इसी दिन शाम 05 बजे से मतगणना की जाएगी। नामांकन पत्र 26 फरवरी से 05 मार्च 2026 तक (सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) सवेरे 11 बजे से दोपहर 03 बजे तक छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन स्थित निर्धारित स्थान पर रिटर्निंग ऑफिसर, सचिव छत्तीसगढ़ विधानसभा, के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे। राज्यसभा चुनाव में राज्य के कुल 90 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वर्तमान विधानसभा संरचना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के 54, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 35 तथा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 01 विधायक मतदान में भाग लेंगे।

छत्तीसगढ़ नल जल योजना की लक्ष्य पूर्ति में हैं 24वें नंबर पर

रायपुर। पंडरिया विधायक भावना बोहरा उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री से जानना चाहा कि पिछले 12 महीनों में कितने जिलों/शहरों में नल जल योजना को जोड़ लिया गया है? कितने जिलों में योजना पूर्ण कर ली गई है? बचे हुए जिलों में कब तक यह योजना पूर्ण कर ली जाएगी? मंत्री अरूण साव ने बताया कि पिछले 12 महीनों में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को नल जल योजना से जोड़ लिया गया है। शहरों में नल जल योजना लागू नहीं है। राज्य के किसी भी जिला में योजना पूर्ण नहीं की गई है। संभावित तिथि बताना संभव नहीं है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ नल जल योजना की लक्ष्य पूर्ति में 24वें नंबर में है।

विधायक बोहरा ने फिर पूछा कि आगामी ग्रीष्मकाल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिए विभाग की क्या योजना है? जिस पर उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्रह ने सदन को बताया कि आगामी ग्रीष्मकाल में

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की कार्य योजना निम्नानुसार है- विभाग में सभी जिलों में हैण्डपंप संधारण के लियेपर्याप्त हैण्डपंप तकनीशियन नियुक्त है। हैण्डपंप संधारण हेतु पर्याप्त मात्रा में हैण्डपंप स्पेयर पार्ट्स एवं 32 मी.मी. व्यास के जी.आई. राईजर पाईप की व्यवस्था सभी जिलों में सुनिश्चित कर ली गई है। ग्रीष्म ऋतु के पूर्व विभाग के द्वारा 15 मार्च से 15 अप्रैल तक एक माह का विशेष हैण्डपंप संधारण अभियान चलाया जायेगा, जिसमें हैण्डपंपों के सुधार कार्य के साथ-साथ जल स्तर से नीचे चले जाने वाले हैण्डपंपों में राईजर पाईप बढ़ाने के साथ पेयजल की गुणवत्ता का सतत् परीक्षण कर पेयजल स्त्रोतों के क्लोरिनेशन का भी कार्य किया जायेगा। विगत वर्ष ग्रीष्म ऋतु में भू-जल स्तर गिरने से पेयजल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हांकित कर वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। ग्रीष्मकाल के दौरान ऐसे क्षेत्र जहां आकस्मिक पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है, वहां तत्काल विभागीय रिंग मशीनों के द्वारा नलकूप खनन कर स्त्रोत तैयार किया जावेगा। आवश्यकतानुसार पेयजल संकट वाले जिलों में ग्रीष्म पूर्व पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 अधिरोपित कराने की कार्यवाही की जायेगी। पेयजल व्यवस्था मॉनिटरिंग हेतु कंट्रोल रूम तैयार कर जिलों के कार्यपालन/सहायक/उप अभियंताओं/ हैण्डपंप तकनीशियनों के मोबाईल नंबरों का समाचार पत्रों में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। पेयजल आपूर्ति के संबंध में संचालित शिकायत निवारण प्रणाली टोल-फ्री नंबर 1916 एवं 1800-233-0008 का जिलों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाया जायेगा।

भाजपा सरकार का बजट समाज के लिए है, जबकि कांग्रेस सरकार के बजट एक परिवार के लिए रहे : केदार कश्यप

कांग्रेस का प्रलाप केवल हताशा और राजनीतिक दीवालिएपन का प्रतीक

■ विकास विरोधी चरित्र एक बार फिर हुआ उजागर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वन व सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा मंगलवार को प्रस्तुत बजट पर कांग्रेस की नकारात्मक प्रतिक्रिया को राजनीतिक दीवालियापन बताया है। श्री कश्यप ने कहा कि जिस कांग्रेस ने पाँच साल तक छत्तीसगढ़ को केवल लूट और भ्रष्टाचार का केंद्र बनाए रखा, उन्हें आज विकास का यह बजट समझ नहीं आ रहा है। दरअसल, प्रदेश की भाजपा सरकार का बजट समाज के सभी वर्गों की भलाई के लिए है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार के

बजट एक ही परिवार के लिए रहे हैं।

प्रदेश के वन मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सर्वतोमुखी कल्याण की दृष्टि से कारगर बजट प्रावधान करके विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का संकल्प व्यक्त किया गया है, लेकिन कांग्रेस के लोग उन योजनाओं, कार्यक्रमों को शुतुरमुर्ग की तरह अपने विरोध की रेत में मुँह छिपाकर अनदेखा करने में लगे हैं। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करना यह सिद्ध करता है कि वे प्रदेश के विकास में केवल बाधा डालना जानते हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। श्री कश्यप ने कटाक्ष किया कि जिस कांग्रेस के शासनकाल में गोबर और कोयले तक में घोटाला हुआ हो, उस कांग्रेस के नेताओं पारदर्शिता और जनकल्याण का यह बजट नकारात्मक ही लगेगा। कांग्रेस को दुःख इस बात का है कि इस बजट में कमीशन के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई है।

कश्यप ने कहा कि आज जब हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधार रही है और हर हाथ को काम व हर खेत को पानी दे रही है, तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख अनर्गल विलाप कर रही है। विष्णुदेव साय की सरकार ने मोदी की गारंटी के हर संकल्प को इस बजट के माध्यम से जमीन पर उतारने का काम किया है। महतारी वंदन योजना से लेकर किसानों को दिए जा रहे बोनस तक, हर वर्ग का सशक्तीकरण कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के इस नकारात्मक रवैये को देख रही है और जनता ही कांग्रेस के प्रलाप का करारा जवाब देगी। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ छत्तीसगढ़ को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

कार्यालय संचालक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग
(इन्द्रावती भवन विभागाध्यक्ष कार्यालय ब्लाक नं.1 द्वितीय तल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर छ.ग.)
E-Mail- govtprintingstationerydept@gmail.com

नवा रायपुर अटल नगर-492002
दूरभाष: कार्यालय 2331302
क्रमांक ESTB-101/61/2025-GOVT. PRINTING AND STATIONARY SECTION/ 1205 दिनांक 20/2/2026

// दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचना पत्र //

कापी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन आपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर, सिंगल कलर सीटफेड आपरेटर, ट्रेसर/रिटेचर/पेस्टर तथा जूनियर रीडर

मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग अंतर्गत कापी होल्डर, प्लेट मेकर, ग्रेनिंग मशीन आपरेटर, फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर, कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर, सिंगल कलर सीटफेड ऑपरेटर, ट्रेसर/रिटेचर/पेस्टर तथा जूनियर रीडर के पदों पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 19.12.2025 को घोषित लिखित परीक्षा परिणाम अनुसार निम्नलिखित पदों पर 1 पद के विरूद्ध 3 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों/ अनुभव/ जाति/निवास/ आय/जन्मतिथि/पहचान पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन निम्न तालिका अनुसार किया जाना है:-

स.क्र.	पद का नाम	निर्धारित दिनांक एवं समय
1	कापी होल्डर	दिनांक 10/03/2026 समय प्रातः 10.30 बजे मे
2	प्लेट मेकर	
3	ग्रेनिंग मशीन आपरेटर	
4	फास्ट डिजिटल प्रिंटर आपरेटर	
5	कनिष्ठ सिंगल कलर मशीन आपरेटर	
6	सिंगल कलर सीटफेड आपरेटर	दिनांक 11/03/2026 समय प्रातः 10.30 बजे से
7	ट्रेसर/रिटेचर/पेस्टर	
8	जूनियर रीडर	

उपरोक्त पदों पर दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची इस विभाग के सूचना पटल पर प्रदर्शित की गई है। दस्तावेज सत्यापन संबंधी विस्तृत जानकारी अभ्यर्थियों के अधिकृत पते पर पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित की गई है।
(संचालक महो. द्वारा अनुमोदित)

संयुक्त संचालक
मुद्रण तथा लेखन सामग्री
छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर

जी-252606861/4

मुफ्त चुनावी उपहार यानी तुष्टीकरण

पूनम आई. कौशिश

मतदाता सावधान हो जाएं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में शीघ्र ही हाई वोल्टेज राजनीतिक तमाशा होने वाला है। अपने बटुए खोल कर रखिए क्योंकि राजनीतिक दल और नेता चुनावी उपहार बांटने की तैयारी में व्यस्त हैं, जिनके अंतर्गत लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा और नि:शुल्क चुनावी उपहार शामिल होंगे। वे इन राजनीतिक उपहारों को वोट प्रतिशत में बदलने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर सामाजिक और आर्थिक उत्थान को वोट के तराजू पर तोला जाएगा क्योंकि तर्कयुक्त नीतियों की बजाय लोकप्रिय उपहार और योजनाओं से बेहतर चुनावी परिणाम प्राप्त होते हैं। यह बात तमिलनाडु द्वारा दायर एक मामले में देश में निःशुल्क उपहारों की संस्कृति के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय की कठोर टिप्पणी के रूप में सामने आई, जहां पर बुधवार को तमिलनाडु ने रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के अपने अधिकार का बचाव किया, जिस पर एक केंद्रीय कानून द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायालय ने राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि वे धनी और निर्धन व्यक्तियों के बीच अंतर किए बिना ऐसी निःशुल्क योजनाएं और उपहार बांट रहे हैं। न्यायालय ने पूछा कि किस प्रकार राजस्व घाटे से जूझ रहे राज्य इस तरह के उपहारों के लिए पैसा लाते हैं। क्या ऐसी कल्याण योजनाएं लक्षित, पारदर्शी और वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम हैं? क्या चुनावों से पहले सरकारी खजाने पर विचार किए बिना आप ऐसी तुष्टीकरण की नीतियां अपना रहे हैं? धनी वर्ग को ऐसी रियायतें क्यों? क्या यह राज्यों का कर्त्तव्य नहीं है कि वे धन को अवसंरचना के विकास पर खर्च करें? गरीबों के लिए आवश्यक सेवाएं ऐसी अविवेकपूर्ण योजनाओं से अलग हैं क्योंकि ऐसी योजनाओं का लक्ष्य केवल चुनावी लाभ होता है। क्या समय नहीं आ गया कि राज्य ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करें? क्या हमारी मेहनत की कमाई के कर के पैसों का उपयोग राजनीतिक दलों को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए करना चाहिए? क्या नेताओं और पार्टियों को ऐसी योजनाओं का पैसा अपनी जेब से नहीं देना चाहिए? क्या ऐसी योजनाएं सबसिडी से अलग हैं? इसका निर्णय कौन करेगा? यह सच है कि संविधान में अनुच्छेद 38 के माध्यम से भारत को एक कल्याणकारी राज्य माना गया है जिसके अंतर्गत राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा दें और असमानता कम करें। अनुच्छेद 39 में यह सुनिश्चित किया गया है कि संसाधनों का समान वितरण हो और संपत्ति का केन्द्रीयकरण रोका जाए। इसलिए ये उपाय तुष्टीकरण नहीं, अपितु जरूरतमंद लोगों के लिए वास्तविक सहायता हैं। यह सच है कि सरकार नि:शुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और नकद अंतरण के माध्यम से कमजोर वर्गों की मदद करती है और उन्हें आर्थिक संकट से बचाती और समावेशी विकास को बढ़ावा देती है तथा दीर्घकाल में सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। क्या ऐसे देश में, जहां पर 70 प्रतिशत लोग गरीबी, असमानता और भूख से जूझ रहे हों, वहां पर ऐसी रियायतें आवश्यक नहीं हैं? क्या नागरिकों की देखभाल करना हमारे नेताओं का कर्त्तव्य नहीं है? किंतु तुष्टीकरण की दृष्टि से आप राजनीतिक शोर-शराबा और आश्वासनों को वास्तविकता समझने की भूल नहीं कर सकते। ये नि:शुल्क उपहार सामान्यता खपत आधारित होते हैं न कि उत्पादकता आधारित, क्योंकि इनका उद्देश्य दीर्घकालीन संपत्ति या आय सृजन क्षमता विकसित करने की बजाय तत्काल भौतिक लाभ पहुंचाना होता है। इसके अलावा ऐसे अत्यधिक नि:शुल्क उपहारों से राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर दबाव पड़ता है।

हेक्सागन गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मायने

कमलेश पांडे

इजरायल द्वारा प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन के अंतर्राष्ट्रीय मायने बेहद दिलचस्प हैं। यह अतिवादी ताकतों के विरूद्ध शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वास्तव में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा प्रस्तावित यह गठबंधन एक ऐसा कूटनीतिक समूह है, जिसमें भारत, अरब देश, अफ्रीकी राष्ट्र, ग्रीस, साइप्रस और अन्य एशियाई देश शामिल होंगे।

समझा जाता है कि भले ही इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य कट्टरपंथी शिया और सुन्नी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके उन वैश्विक कूटनीतिक निहितार्थों से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जो अमेरिका, चीन और रूस जैसे तीनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के कान खड़े करने वाले साबित हो सकते हैं।

ऐसा इसलिए कि इस गठबंधन में विश्व की चौथी बड़ी शक्ति भारत बेहद मजबूत और नेतृत्वकारी स्थिति में रहेगा। लिहाजा इसका स्वरूप तय हो जाने के बाद अरब और खाड़ी के इस्लामिक देशों पर वर्चस्व की जो होड़ वैश्विक महाशक्तियों के बीच मची रहती है, उस पर एक हद तक अल्पविराम भी लगेगा।

दरअसल, हेक्सागन गठबंधन छह-पक्षीय (हेक्सागन) धुरी है जो पश्चिम एशिया में नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप से भी इसे पूरी ताकत मिलेगी। यह भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) से भी जुड़ी हुई है।

वहीं इस बेमिसाल गठबंधन में भारत को प्रमुख भूमिका दी गई है, जिसमें एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुरक्षा सहयोग पर फोकस होगा। जहां तक भारत की भागीदारी की बात है तो भारत अभी आधिकारिक रूप से इसमें शामिल नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी की 25-26 फरवरी 2026 को होने वाली इजरायल यात्रा के दौरान इस पर चर्चा और समझौते होने की संभावना बलवती है।

समझा जाता है कि यह 2017 के बाद पीएम मोदी की यह दूसरी बड़ी यात्रा होगी, जो पारस्परिक संबंधों को और अधिक मजबूत करेगी। वहीं नेतन्याहू ने इसे कट्टरपंथ विरोधी नई धुरी बताया है। उल्लेखनीय है कि हेक्सागन

गठबंधन अभी औपचारिक रूप से अस्तित्व में नहीं आया है, लेकिन इसमें शामिल होने वाले प्रमुख देशों या समूहों में इजरायल, भारत, ग्रीस, साइप्रस, कुछ अरब राष्ट्र और अफ्रीकी देश शामिल बताए गए हैं।

इस गठबंधन का मुख्य देश इजरायल है जो गठबंधन का प्रस्तावक और केंद्र बिंदु है। जबकि भारत इसके प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जा रहा है, खासकर सुरक्षा और तकनीकी सहयोग के लिए। वहीं ग्रीस और साइप्रस इसके भूमध्यसागरीय रणनीतिक साझेदार देश हैं। जबकि अरब के कतिपय देश विकास और शांति समर्थक राष्ट्र के तौर पर रहेंगे। वहीं अफ्रीकी देश क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसमें शामिल होंगे। जबकि अन्य एशियाई देश इसमें भारत और उस जैसे सहयोगी की भूमिका में शामिल किए जाएंगे।

जहां तक हेक्सागन गठबंधन के उद्देश्य की बात है तो यह गठबंधन कट्टरपंथी शिया-सुन्नी ताकतों के खिलाफ एकजुटता का प्रयास है, जिसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे से जुड़ाव हो सकता है। वहीं इसका मुख्य ध्येय कट्टरपंथी शिया और सुन्नी ताकतों (जैसे ईरान समर्थित शिया धुरी और उभरती सुन्नी कट्टरपंथी शक्तियों) के खिलाफ एकजुट होकर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है।

यह गठबंधन भूमध्य सागर, मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया के सहयोगी देशों को एक मंच पर लाकर कट्टरपंथ, आतंकवाद और अस्थिरता का सामना करने का एक सशक्त प्रयास है। इसमें भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) को मजबूत करना, एआई, क्वांटम तकनीक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

देखा जाए तो हेक्सागन गठबंधन की भावी योजनाओं से चीन के बीआरआई जैसे प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। इसका अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि एक नई वैश्विक धुरी बनाने का जो नेतन्याहू का विजन है, वो विकास-समर्थक राष्ट्रों को शांति और समृद्धि के लिए एकजुट करने वाला है। इसलिए भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

यही वजह है कि हेक्सागन गठबंधन से भारत को वैश्विक महाशक्ति के केंद्र के रूप में उभरने में रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी लाभ मिलेंगे। क्योंकि यह नया नाटो जैसा समूह भारत को मध्य पूर्व-यूरोप तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करेगा। लिहाजा, इस नई स्थिति का प्रमुख लाभ रणनीतिक ऊंचाई प्राप्त करना है।

इससे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में भारत की गिनती बढ़ेगी, और कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बनेगा। यह इसलिए भी जरूरी है कि अमेरिका-चीन जैसे अहम वैश्विक खिलाड़ी अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद के द्वंद्व में उलझे हुए हैं।

जहां तक भारत की आर्थिक पहुंच की बात है तो आईएमईसी गलियारे से मिडिल ईस्ट-यूरोप तक सीधा सुरक्षित मार्ग मिलेगा, जो चीन के बीआरआई को चुनौती देता हुआ प्रतीत होगा।वहीं भारत को तकनीकी सहयोग मिलेगा। खासकर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस (मिसाइल, ड्रोन) और सुरक्षा साझेदारी मजबूत होगी।

इसका क्षेत्रीय प्रभाव यह पड़ेगा कि अरब-अफ्रीकी देशों से भारत के संबंध मजबूत होंगे, और अमेरिका के बिना भी भारत का स्वतंत्र सुरक्षा तंत्र मजबूत बना रहेगा। वहीं अपेक्षित प्रभाव यह होगा कि पीएम मोदी की इजरायल यात्रा से ये सभी लाभ औपचारिक हो सकते हैं, जो भारत को वैश्विक पावर बैलेंस में मजबूत बनाएंगे।

सच कहूं तो हेक्सागन गठबंधन चीन के लिए चुनौती है क्योंकि यह चीन के वन बेल्ट वन रोड (बीआरआई) प्रोजेक्ट को सीधे चुनौती देगा। खासकर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) को मजबूत कर यह वैकल्पिक व्यापार मार्ग बनाएगा। इसका प्रमुख कारण आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। आईएमईसी से मिडिल ईस्ट-यूरोप तक चीन-बिना सीधा रास्ता, बीआरआई के प्रभाव को कम करेगा।

इस नए गठबंधन से चीन की रणनीतिक घेराबंदी भी आसान होगी, क्योंकि नया एशियाई-अरब-अफ्रीकी देशों का समूह चीन के मध्य पूर्व विस्तार को रोकेगा। जहां तक भारत की भूमिका की बात है तो भारत को महाशक्ति केंद्र बनाकर चीन के क्षेत्रीय वर्चस्व को चुनौती दी जा सकती है। जबकि तकनीकी व सुरक्षा के दृष्टिगत एआई, क्वांटम सहयोग से चीन की तकनीकी श्रेष्ठता पर असर पड़ेगा।

जहां तक वैश्विक प्रभाव की बात है तो यह क्वाड/आईएमईसी जैसी पहलों का विस्तार बनेगा, जो चीन के विस्तारवाद को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है।

हां, हेक्सागन गठबंधन क्वाड और एयूकेयूएस से स्पष्ट रूप से अलग है। यह इजरायल-प्रमुखित मध्य पूर्व-केंद्रित रणनीतिक समूह है, जबकि क्वाड और एयूकेयूएस इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित हैं।

देखा जाए तो हेक्सागन गठबंधन, क्वाड और एयूकेयूएस के क्षेत्र, उनमें शामिल देश, उनका उद्देश्य व प्रकृति सबकुछ अलग-अलग है। जहां तक क्षेत्र की बात है तो हेक्सागन गठबंधन मध्य पूर्व, भूमध्य सागर व अफ्रीका-एशिया में सक्रिय होगा, जबकि क्वाड गठबंधन इंडो-पैसिफिक में चीन पर फोकस करते हुए सक्रिय है, जबकि क्वाड और एयूकेयूएस इंडो-पैसिफिक (सुरक्षा) से जुड़ा गठबंधन है।

जहां तक देशों की बात है तो हेक्सागन गठबंधन में इजरायल, भारत, ग्रीस, साइप्रस, अरब-अफ्रीकी राष्ट्र शामिल होंगे। जबकि क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं क्वाड और एयूकेयूएस गठबंधन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटेन शामिल हैं।

जहां तक उद्देश्य की बात है तो हेक्सागन गठबंधन का ध्येय कट्टरपंथ विरोध, आईएमईसी और एआई-सुरक्षा है। जबकि क्वाड का ध्येय खुला हिंद महासागर व जलवायु-सहयोग हैं। वहीं एयूकेयूएस का ध्येय परमाणु पनडुब्बी व सैन्य तकनीक सहयोग है।

जहां तक इन गठबंधनों की प्रकृति की बात है तो हेक्सागन गठबंधन प्रस्तावित छह-पक्षीय धुरी है। जबकि क्वाड अनौपचारिक वार्ता मंच है। वहीं एयूकेयूएस औपचारिक सैन्य गठबंधन है, जो चीनी वर्चस्व को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है।

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

त्रिदेव और अनसूय

कुछ महाशय भविष्य पुराण (प्रतिसर्ग खण्ड 4 अध्याय 17) के आधार पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के ऊपर यह भी मिथ्या कलंक लगाया करते हैं कि उक्त देवत्रय ने अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी अनसूया के साथ व्यभिचार किया। हम इस आक्षेप की असलियत प्रकट करने के लिए पाठकों के सामने सर्वप्रथम पौराणिक स्वरूप रखते हैं, जिससे मूल शब्दों के पड़ने मात्र से बहुत कुछ सन्देह काफूर हो जायगा ।

पौराणिक स्वरूप

कदाचिद् भगवानत्रिर्ग ङ्गाकूलेऽनसूयया।
सार्ध तपो महत्कुर्वन्ब्रह्मध्यानपरोऽभवत्।। 67।।
तदा ब्रह्मा हरिश्शम्भुः स्वस्ववाहनमास्थिताः।
वरं ब्रूहीति वचनं तमाहुस्ते सनातनाः ॥68।।
इति श्रुत्वा वचस्तेषां स्वयम्भूतनयो मुनिः।
नैव किञ्चिद् वचः प्राह संस्थितः परमात्मनि।। 69।।
तस्य भावं समालोक्य त्रयो देवाः सनातनाः।
अनसूयां तस्य पत्नीं समागम्य वचोऽब्रुवन्।।70॥
लिङ्गहस्तः स्वयं रुद्रो विष्णुस्तद्रसवर्द्धनः।
ब्रह्मा कामब्रह्मलोपः स्थितस्तस्या वशंगतः।।
रति देहि मदाघूर्णे!
नो चेत्प्राणांस्त्यजाम्यहम् ।।71।।
पतिव्रताऽनसूया च श्रुत्वा तेषां वचोऽशुभम्।
नैव किञ्चिद् वचः प्राह कोपभीता सुरान्प्रति।।72।।
मोहितास्तेऽत्र ते देवा गृहीत्वा तां बलात्तदा।
मैथुनाय समुद्योगं चक्रुर्मायाविमोहिताः ॥73॥
तदा क्रुद्धा सती सा वै तांच्छशाप मुनिप्रिया।
मम पुत्रा भविष्यन्ति यूयं कामविमोहिताः।।74।।
महादेवस्य वै लिङ्ग ब्रह्मणोऽस्य महाशिरः।
चरणौ वासुदेवस्य पूजनीया नरैः सदा।
भविष्यन्ति सुरश्रेष्ठा ! उपहासोऽयमुत्तमः ॥75।।

क्रमशः ...

वीर सावरकर

अनन्या मिश्रा

भारत में ऐसे तमाम वीर सेनानी हुए, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने अपना सबकुछ देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही एक महापुरुष वीर सावरकर थे। आज भी भारत में वीर सावरकर को देश एक भारतीय राष्ट्रवादी के रूप में जानता है। बता दें कि 28 मई को वीर सावरकर का जन्म हुआ था। राजनीतिक दल और राष्ट्रवादी संगठन हिंदू महासभा के प्रमुख सदस्य रहकर वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया था।

सावरकर के मन में बचपन से ही देश भक्ति का भाव देखने को मिला था। उन्होंने अपनी वीरता का परचम महज 12 साल की उम्र में लहरा दिया था। बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर मुसलमानों की भीड़ में 1 छात्रों के समूह को भगा दिया। जिसने पूरे शहर में अफरा-तफरी मचा रखी थी। उनके इस कार्य के लिए सावरकर की बहुत प्रशंसा हुई। इसके बाद ही उनको वीर नाम दिया गया। तभी से उन्हें वीर सावरकर कहकर पुकारा जाने लगा।

सावरकर ने अपने बड़े भाई गणेश के साथ मिलकर इंडियन कॉउन्सिल एक्ट 1909 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इस विरोध के लिए सावरकर को अपराधी घोषित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने सावरकर पर अपराध की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। वहीं गिरफ्तारी से बचने के लिए वह पेरिस चले गए। लेकिन बाद में साल 1910 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कराया गया। इस केस की सुनवाई के लिए सावरकर को मुंबई भेज दिया गया। जहां पर उनको 50 साल की सजा सुनाई गई। जिसके बाद साल 1911 को काला पानी की सजा के तौर पर उन्हें अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया। इस दौरान उनको काफी ज्यादा प्रताड़ित किया गया। लेकिन सावरकर ने हार नहीं मानी।

बताया जाता है कि जब सावरकर को सजा सुनाई गई तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने एक याचिका दी थी। जिसके अनुसार, यदि उन्हें छोड़ दिया जाता है तो वह देश की स्वतंत्रता आंदोलनों में हिस्सा नहीं लेगें और अंग्रेज सरकार के वफादार बनकर रहेंगे। जेल की सजा पूरी होने के बाद सावरकर ने अपना वादा नहीं तोड़ा और वह किसी गतिविधि में शामिल नहीं हुए। हालांकि इस माफीनामे का क्या सच है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता रहता है। जहां एक ओर भारत सरकार वीर सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि वीर सावरकर भारत रत्न के काबिल नहीं है।

वीर सावरकर ने अपनी इच्छा मृत्यु का प्रण लिया था। इसलिए उन्होंने पहले ही सबको बता दिया था कि वह अपनी मृत्यु तक उपवास पर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। बता दें कि 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने घोषणा कर दी कि वह आज से उपवास रखेंगे। जिसके बाद उपवास का पालन करते हुए 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।

पैक्स सिलिका में भारत का होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि

ललित गर्ग

इक्कीसवीं सदी का यह दौर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धा का दौर बन चुका है। ऐसे समय में भारत द्वारा एआई शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन और उसके तुरंत बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले समूह पैक्स सिलिका से औपचारिक रूप से जुड़ना केवल एक कूटनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी और रणनीतिक कदम है। यह उस नए भारत की घोषणा है जो तकनीकी शक्ति, नैतिक दृष्टि और वैश्विक संतुलन-तीनों को साथ लेकर चलने का सामर्थ्य अर्जित कर रहा है। एआई समिट के माध्यम से भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह अब केवल तकनीक का उपभोक्ता राष्ट्र नहीं, बल्कि निर्माता और मार्गदर्शक की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। दुनिया की तीसरी बड़ी एआई शक्ति बनने की दिशा में यह एक ठोस चरणन्यास है।

दुर्लभ खनिजों और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर चीन का लगभग 90 प्रतिशत वर्चस्व पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। कंप्यूटर चिप से लेकर रक्षा प्रणालियों और अंतरिक्ष तकनीक तक, हर क्षेत्र इन संसाधनों पर निर्भर है। इस पृष्ठभूमि में पैक्स सिलिका जैसे मंच की परिकल्पना एक संतुलित, विश्वसनीय और बहु-ध्रुवीय तकनीकी ढांचे के रूप में की गई है। भारत का इस समूह में शामिल होना केवल प्रतीकात्मक कदम नहीं, बल्कि रणनीतिक और अनिवार्य निर्णय है। भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, विशाल युवा प्रतिभा और उभरता हुआ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इस गठबंधन को नई मजबूती प्रदान करेगा। यह पहल किसी के विरुद्ध आक्रामकता नहीं, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में संतुलन और विविधता स्थापित करने का प्रयास है। जब शक्ति का केंद्रीकरण टूटता है और साझेदारी का विस्तार होता है, तभी विश्व व्यवस्था स्थिर और संतुलित बनती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक

दशक में भारत ने तकनीक को शासन और विकास के केंद्र में स्थापित किया है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों ने एक मजबूत आधार तैयार किया है। भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। आधार, यूपीआई और डिजिटल सेवाओं ने करोड़ों लोगों को आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ा है। इसी आधार पर एआई और चिप निर्माण के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की सक्रियता और वैश्विक मंचों पर भारत की प्रभावी उपस्थिति ने देश को एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित किया है। उनका दृष्टिकोण केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता को वैश्विक सहयोग के साथ जोड़ने का है।

भारत में चिप डिजाइन, निर्माण और एआई अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बड़े निवेश आकर्षित किए जा रहे हैं। वैश्विक कंपनियाँ भारत को स्थिर लोकतंत्र, कुशल मानव संसाधन और दीर्घकालिक नीति स्थिरता वाले देश के रूप में देख रही हैं। पैक्स सिलिका जैसे अंतरराष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा बनने से भारत को तकनीकी सहयोग, संयुक्त अनुसंधान, पूंजी निवेश और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण में व्यापक लाभ मिलेगा। इससे न केवल चीन पर निर्भरता कम होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता भी सुदृढ़ होगी। यह भागीदारी भारत को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देशों जैसी प्रमुख तकनीकी शक्तियों के साथ और अधिक निकटता से जोड़ेगी, जिससे वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ेगी। भारत की विशेषता केवल तकनीकी क्षमता नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और नैतिक दृष्टि भी है। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना से प्रेरित भारत एआई को मानव-केंद्रित विकास का माध्यम बनाना चाहता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से व्यापक जनकल्याण सुनिश्चित किया जा सकता है। यदि तकनीक कुछ शक्तियों के हाथों में सिमट जाए तो असंतुलन बढ़ता है, किंतु जब लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र इसका नेतृत्व करते हैं तो यह वैश्विक कल्याण का साधन बन सकती है। भारत का प्रयास है कि एआई के नैतिक मानदंड सार्वभौमिक हों और तकनीक का उपयोग हथियार के रूप में नहीं, बल्कि मानव प्रगति के साधन के रूप में हो।

भारत की दृष्टि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल तकनीकी प्रगति का उपकरण नहीं, बल्कि मानवीय चेतना के विस्तार का माध्यम है। जिस देश ने विश्व को ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' का मंत्र दिया, जिसने करुणा, अहिंसा और सह-अस्तित्व की परंपरा को जीवन-मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, वह एआई को भी केवल बाज़ार और प्रभुत्व की प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि मानव कल्याण और वैश्विक संतुलन के संदर्भ में देखता है। भारत की सभ्यता-चेतना, जो महात्मा गांधी की अहिंसा और गौतम बुद्ध की करुणा से अनुप्राणित है, तकनीकी विकास को नैतिक अनुशासन से जोड़ने की प्रेरणा देती है। यहाँ विकास का अर्थ केवल गति नहीं, बल्कि दिशा भी है; केवल क्षमता नहीं, बल्कि संवेदना भी है। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जीवन की समग्रता-प्रकृति, समाज और मानव गरिमा के साथ जोड़ा जाए, तो भारत विश्व संरचना में ऐसा संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर सकता है जो तकनीक को विनाश का कारण बनने से रोककर उसे सृजन, समावेशन और मानव उत्कर्ष का सशक्त साधन बना दे।

आज दुनिया दो ध्रुवों के बीच खड़ी दिखाई देती है-एक ओर केंद्रीकृत तकनीकी वर्चस्व, दूसरी ओर साझेदारी और संतुलन का मॉडल। भारत का उभार इस द्वंद्व को संतुलन में बदलने की क्षमता रखता है। भारत न टकराव की राह पर है, न निष्क्रियता कीय वह सक्रिय संतुलन की नीति अपना रहा है। यह संतुलन ही भविष्य की शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का आधार बन सकता है। पैक्स सिलिका के माध्यम से भारत और उसके सहयोगी एक ऐसी नई दिशा दे सकते हैं जहाँ तकनीकी नवाचार का लाभ वैश्विक दक्षिण तक पहुँचे, आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शी हो और वैश्विक शक्ति-संतुलन स्थिर रहे। निस्संदेह, यह समय भारत के लिए ऐतिहासिक है। एआई और सेमीकंडक्टर के इस युग में भारत का यह कदम उसकी आर्थिक और तकनीकी शक्ति को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उभरती यह तकनीकी और एआई क्रांति न केवल भारत को सशक्त बना रही है, बल्कि विश्व को भी संतुलन और सहयोग की नई राह दिखा रही है। आने वाले वर्षों में यह साझेदारी नई सृष्टि का आधार बन सकती है-एक ऐसी सृष्टि जहाँ तकनीक प्रतिस्पर्धा का नहीं, बल्कि समन्वय और शांति का माध्यम बने। भारत इस दिशा में दृढ़ता से अग्रसर है और विश्व नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए स्वयं को सक्षम बना रहा है।

आज का इतिहास

1925 तुर्की सरकार के खिलाफ जेहाद शुरू हुआ।
1952 विन्सेन्ट मैसी ने कनाडा के पहले गवर्नर-गवर्नर जेनरल के रूप में शपथ ली।
1958 पाकिस्तान के कोट दी जी सिंध प्राप्त के स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष बरामद हुए जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी लगभग तीन सौ वर्ष पुराने थे।
1993 न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर बम हमले में छह लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हो गए।
1995 व्यापारी निक लेसन द्वारा सिंगापुर में नुकसान के बाद, बैरिंग्स का लंदन वित्त घर ढह गया।
1997 दुनिया को बदलें बेबीफेस, बेक और लेनन रोमिस ने 39 वें ग्रैमी पुरस्कार जीते।
1998 वेनेजुएला - प्रशांत महासागर में पूर्ण सूर्य ग्रहण (4m09) देखा गया।
1999 पांच ग्रैमी अवार्ड जीतकर रैप गायिका लॉरिन हिल ने नया रिकार्ड बनाया।
2001 क्रिकेट के महानतम खिलाड़ी सर डॉन ब्रैडमैन का निधन हुआ।
2003 लंदन कंजेशन चार्ज योजना शुरू की गयी।
2004 मैसेडोनिया के राष्ट्रपति बेरिस ट्रेज कोवस्की की विमान दुर्घटना में मृत्यु हुई।
2007 नेपाल सरकार द्वारा नरेश की सम्पत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की घोषणा हुई।
2008 कोरियाई युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तर कोरिया की पहली महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा में, न्यूयॉर्क फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा ने पूर्वी प्योंगयांग ग्रैंड थियेटर में प्रदर्शन किया।
2009 कोसोवो युद्ध के दौरान, सर्बिया के पूर्व राष्ट्रपति मिलन मुलुतिनोविच युद्ध संकट से बरी हो गए।
2010 आत्मघाती हमलावरों द्वारा किए गए हमलों की संख्या के कारण अफगानिस्तान के काबुल में 17 लोग मारे गए।
2011 कनाडाई राजनेता क्रिस्टी क्लार्क, ब्रिटिश कोलंबिया बैलट की लिबरल पार्टी जीतने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया की प्रमुख बनने वाली दूसरी महिला बनीं।
2012 दुनिया का समाचार जो फोन हैकिंग विवाद के कारण बंद हो गया है उसे नए सहयोग से रविवार को सूरज से बदलने की घोषणा की गई है।
2013 अमेरिका, चीन, जर्मनी, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन के प्रतिनिधियों के साथ ईरान के अधिकारी ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करते हैं।

सहयोग का नया मॉडल : भारत-ब्राजील के लिए परस्पर लाभ

आनंद कुमार

ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की हालिया भारत यात्रा ने भारत-ब्राजील संबंधों को एक नए चरण में प्रवेश करा दिया है। वर्ष 2006 में स्थापित सामरिक साझेदारी को अब दोनों देशों ने व्यापक, बहुस्तरीय और दीर्घकालिक सहयोग में बदलने का निर्णय लिया है। यह केवल एक औपचारिक राजकीय यात्रा नहीं थी, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में दो प्रमुख उभरती शक्तियों द्वारा अपने हितों की रक्षा और विस्तार के लिए उठाया गया रणनीतिक कदम था। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी विस्तृत वार्ता ने स्पष्ट कर दिया कि दोनों देश अपने संबंधों को केवल प्रतीकात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि ठोस नीतिगत आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की संरक्षणवादी और अस्थिर टैरिफ नीतियों ने कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को झटका दिया है। भारत व ब्राजील, दोनों अमेरिकी बाजार से जुड़े हैं और अचानक बढ़ाए गए शुल्कों ने उनके निर्यात को प्रभावित किया है। ऐसे में, यदि वैश्विक दक्षिण के देश अपने आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करना चाहते हैं, तो उन्हें पारंपरिक पश्चिमी बाजारों पर निर्भरता कम करके परस्पर सहयोग को सुदृढ़ करना होगा। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा की यह यात्रा इसी रणनीतिक पुनर्संतुलन का हिस्सा प्रतीत होती है।

दोनों देशों ने वर्ष 2025 में लगभग 15 अरब डॉलर को पार कर चुके द्विपक्षीय व्यापार को अब 2030 तक 30 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यह केवल संख्यात्मक वृद्धि का संकेत नहीं, बल्कि संरचनात्मक परिवर्तन की इच्छा को दर्शाता है। गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने, एंटी-डंपिंग मुद्दों पर संवाद बढ़ाने और भारत-मर्कोसुर वरीयता प्राप्त व्यापार समझौते का विस्तार करने पर सहमति इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। लैटिन अमेरिका में ब्राजील भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों अर्थव्यवस्थाओं की पूरक प्रकृति इस लक्ष्य को यथार्थवादी बनाती है। खनिज और इस्पात क्षेत्र में सहयोग इस यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है। भारत अपनी अवसंरचना, औद्योगिकीकरण और विनिर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है, जिसके लिए लौह अयस्क और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की निरंतर आपूर्ति

आवश्यक है।

ब्राजील विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादकों में से एक है और उसके पास दुर्लभ मृदा तत्वों सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। चीन पर निर्भरता कम करना भारत की रणनीतिक प्राथमिकता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आपूर्ति श्रृंखला का नियंत्रण कुछ सीमित देशों के पास है। ऐसे में, खनन और खनिज सहयोग समझौता भारत को संसाधन सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जबकि यह ब्राजील को स्थायी और विस्तारित बाजार उपलब्ध कराएगा। यह सहयोग केवल कच्चे माल के आयात-निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्वेषण, तकनीकी निवेश और इस्पात अवसंरचना के विकास को भी शामिल करता है। डिजिटल और तकनीकी सहयोग भी इस रिश्ते का उभरता हुआ स्तंभ है।

एआई इम्पैक्ट समिट में राष्ट्रपति लूला ने एआई के अंतरराष्ट्रीय नियमन और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत विकासोन्मुख वैश्विक शासन की आवश्यकता पर बल दिया। भारत, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभरा है, इस दृष्टिकोण के साथ सामंजस्य रखता है। डिजिटल साझेदारी की संयुक्त घोषणा के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह पहल दर्शाती है कि दोनों देश वैश्विक तकनीकी मानकों के निर्माण में सक्रिय भागीदारी चाहते हैं।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ हुआ है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के रखरखाव में सहयोग, रक्षा औद्योगिक सह-निर्माण और संभावित एयरोस्पेस निवेश इस बढ़ते विश्वास के प्रमाण हैं। आतंकवाद, आतंकी वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग ने इस साझेदारी को मजबूती प्रदान की है। ऐसे वक्त में, जब साइबर खतरे और समुद्री चुनौतियां बढ़ रही हैं, इस प्रकार का सहयोग दोनों देशों की सामरिक स्वायत्तता को सुदृढ़ करता है। भारत की सस्ती जेनेरिक दवाओं की वैश्विक प्रतिष्ठा और ब्राजील की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की आवश्यकताएं एक-दूसरे की पूरक हैं। दोनों देशों के नियामक निकायों के बीच समझौते से दवाओं और टीकों के स्थानीय उत्पादन, अनुसंधान सहयोग और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन में समान दवा पहुंच के समर्थन का संयुक्त रुख इस साझेदारी को वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति से भी जोड़ता है।

ऊर्जा संक्रमण और जलवायु सहयोग के क्षेत्र में भी व्यापक सहमति बनी है। हरित हाइड्रोजन, सतत विमानन ईंधन और स्वच्छ ऊर्जा निवेश में सहयोग से दोनों देशों को जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के साथ-साथ आर्थिक अवसर भी मिल सकते हैं। दोनों देश जलवायु कार्रवाई को केवल पर्यावरणीय प्रतिबद्धता नहीं, बल्कि हरित औद्योगिक विकास के अवसर के रूप में देख रहे हैं।

बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए पारस्परिक समर्थन लंबे समय से दोनों देशों की प्राथमिकता रहा है। ब्रिक्स और अन्य मंचों पर समन्वय से भारत और ब्राजील वैश्विक दक्षिण की आवाज को अधिक सशक्त बनाने के इच्छुक हैं। स्थानीय मुद्राओं में व्यापार की संभावना पर विचार इस दिशा में एक सावधानीपूर्ण कदम है, जो वित्तीय विविधीकरण की ओर संकेत करता है। दीर्घकालिक वीजा सुविधा, छात्र आदान-प्रदान और सांस्कृतिक सहयोग से पारस्परिक समझ और विश्वास को बढ़ावा मिलेगा। किसी भी सामरिक साझेदारी की सफलता अंततः सामाजिक और मानवीय जुड़ाव पर निर्भर करती है।

समग्रता में देखें तो, भारत-ब्राजील संबंध सकारात्मक दिशा में अग्रसर है, परंतु इस गति को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होगा। घोषित लक्ष्यों और हस्ताक्षरित समझौतों को ठोस परिणामों में बदलना ही वास्तविक परीक्षा होगी। यदि दोनों देश अपने संकल्प को व्यावहारिक रूप दें, तो यह 'विन-विन' साझेदारी न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देगी, बल्कि वैश्विक दक्षिण के लिए सहयोग का एक सशक्त और व्यावहारिक मॉडल भी प्रस्तुत करेगी।

पैक्स सिलिका और भारत : चुनौती है चीन और वही कामयाबी का पैमाना

लव गौर

हाल ही में भारत द्वारा पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल में उसका औपचारिक तौर पर शामिल होना रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और तकनीक आपूर्ति श्रृंखला में चीन के बढ़ते प्रभुत्व का मुकाबला करना है। उल्लेखनीय है कि ट्रंप प्रशासन ने पिछले वर्ष दिसंबर में इस समूह की शुरुआत की थी, पर प्रारंभिक सूची में भारत को शामिल नहीं किया गया था।

हालांकि, एआई शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का यह कहना वैश्विक परिदृश्य में भारत के बढ़ते कद को ही दर्शाता है कि भारत प्रतिभा का भंडार है और इसकी इंजीनियरिंग क्षमताएं इस गठबंधन को मजबूत ही बनाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पैक्स सिलिका में भारत का प्रवेश महज प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक और आवश्यक भी है। नहीं भूलना चाहिए कि दुर्लभ खनिजों के वैश्विक उत्पादन में 90 फीसदी की हिस्सेदारी रखने वाला चीन पिछले कुछ वर्षों में एआई और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के मामले में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है, जिसे अमेरिका अपने लिए एक बड़ी चुनौती मान रहा है।

गौरतलब है कि आज ये दुर्लभ खनिज कंप्यूटर चिप से लेकर कार व मिसाइल बनाने तक काम आते हैं और यही वजह है कि इस मामले में चीन पर निर्भरता को भारत समेत कई देश अपनी सामरिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी चिंता का विषय मान रहे हैं। खासकर, भारत के लिए यह भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे देश के तकनीकी और आर्थिक भविष्य से जुड़ी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों

व अवसरों का सीधा समाधान हो सकेगा।

उल्लेखनीय है कि भारत ने चिप डिजाइन, निर्माण तथा एआई शोध को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किए हैं और इससे जुड़ी परियोजनाओं के लिए काफी निवेश भी आकर्षित किया है। एक अंतरराष्ट्रीय ढांचे का हिस्सा होने से भारत को अधिक निवेश, तकनीक सहयोग और संयुक्त अनुसंधान साझेदारी को आकर्षित करने में तो मदद मिलेगी ही, उसके तकनीक बुनियादी ढांचे में पूंजी लगाने पर विचार कर रही वैश्विक कंपनियों का भी भरोसा बढ़ेगा।

कुल मिलाकर, यह भारत को अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय साझेदारों जैसी प्रमुख तकनीक शक्तियों से घनिष्ठता से जोड़ेगा। लिहाजा, यह कदम वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है। देखने वाली बात होगी कि चीन इस पर क्या रुख अपनाता है, जिसके साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। हालांकि, ट्रंप जिस तेजी से अपनी योजनाएं बदलते रहते हैं, उसे देखते हुए पैक्स सिलिका की कामयाबी उनके रुख के साथ इस बात पर भी निर्भर करेगी कि इसके साझेदार केवल बातचीत पर निर्भर न रहकर एक ठोस व सुरक्षित तकनीकी नेटवर्क के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें।

16वां वित्त आयोग: समर्थ राज्यों को प्रोत्साहन

अजित रानाडे

भारत का राजकोषीय संघवाद दिखने में सरल एक समझौते पर चलता है। संघ व्यापक करों का अधिकांश हिस्सा एकत्र करता है, जबकि राज्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, स्कूल, अस्पताल, पुलिसिंग, स्थानीय सड़कें, जलापूर्ति और बहुत कुछ की अग्रिम पंक्ति की जिम्मेदारी निभाते हैं। कर राजस्व और व्यय दायित्वों में मेल नहीं है। राज्यों पर लगभग दो-तिहाई व्यय दायित्व हैं, पर केवल एक-तिहाई राजस्व पर उनका नियंत्रण है। इसलिए संविधान ने एक निष्पक्ष मध्यस्थ, वित्त आयोग का प्रावधान किया, जो समय-समय पर यह अनुशंसा करता है कि केंद्रीय करों के बांटे जाने वाले हिस्से को संघ और राज्यों के बीच तथा राज्य बनाम राज्य के बीच कैसे बांटा जाये।

वित्त आयोग का पुनर्गठन हर पांच वर्ष में किया जाता है, ताकि विभाजन का फॉर्मूला हमेशा के लिए स्थिर रहने के बजाय बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप ढल सके। आयोग का मुख्य कार्य अनुच्छेद 280 से आता है और सिफारिशों का कार्यान्वयन अनुच्छेद 281 से। व्यवहार में वित्त आयोग के निर्णय भारतीय संघवाद के वित्तीय 'ऑपरेटिंग सिस्टम' बन जाते हैं। वे राज्यों को मिलने वाली मासिक नकदी, कल्याणकारी और पूंजीगत खर्च के लिए उनके बजट की जगह, और उनकी उधार लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। अब जब 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर संसद के समक्ष पेश कर दिया है, नया फॉर्मूला 2026-31 की अवधि में केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंधों को आकार देगा।

मुख्य प्रश्न 'किसे कितना मिलेगा' का नहीं है, बल्कि यह भी है कि यह व्यवस्था किस प्रकार के प्रोत्साहन पैदा करती है- खासकर ऐसे संघीय ढांचे में जहां समृद्धि और राजनीतिक शक्ति असमान रूप से वितरित हैं। पिछले आयोग की तरह 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41 फीसदी पर बरकरार रखी है। बाईस राज्यों की मांग थी कि राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 फीसदी की जाये। यह उनकी उस शिकायत के कारण था, जो केंद्र द्वारा 'सेस' और 'सरचार्ज' पर बढ़ती निर्भरता

से जुड़ी है, जो आम तौर पर विभाज्य पूल से बाहर होते हैं, इसलिए साझा नहीं किये जाते। चूंकि विभाज्य पूल का कुल आकार 16वें वित्त आयोग की अवधि में 55 ट्रिलियन से करीब दोगुना होकर 90 ट्रिलियन रुपये हो जायेगा, इसलिए राज्यों के पास काफी अधिक संसाधन होंगे। पर अगर केंद्र गैर-साझा लेवी का विस्तार जारी रखता है, तो यह 41 प्रतिशत हकीकत में आंकड़ों से कम महसूस हो सकता है।

सोलहवें वित्त आयोग का सबसे चौंकाने वाला नवाचार क्षैतिज (राज्यों के बीच) वितरण में है = इसने 10 फीसदी वेटेज के साथ 'राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में योगदान' को एक मानदंड के रूप में पेश किया है। आयोग ने अन्य जगहों पर वेटेज कम कर ऐसा किया है। यह उन राज्यों के लिए पुरस्कार है, जो राष्ट्रीय उत्पादन में अधिक योगदान देते हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ट्रांसफर की नैतिक भाषा बदलती है। दशकों तक प्रमुख तर्क यह रहा कि आय और क्षमता में भिन्नताओं के बावजूद राज्यों को तुलनीय बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में मदद करना और संरचनात्मक कमियों की भरपाई करना।

पर नया जीडीपी-योगदान मानदंड कहता है कि प्रदर्शन और योगदान भी मायने रखते हैं। संवैधानिक रूप से आयोग का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि साझा करों का न्यायसंगत वितरण हो, ताकि विभिन्न स्तर की सरकारें संविधान द्वारा सौंपे गये दायित्व निभा सकें। 'जीडीपी में योगदान' जोड़ना असंवैधानिक नहीं है। पर कर वितरण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीडीपी-योगदान का प्रावधान राजस्व-असमर्थता के तर्क से टकरा सकता है। सभी राज्य समान स्थिति में नहीं हैं। समृद्ध राज्य के पास बेहतर ढांचागत सुविधा और संस्थान होते हैं, जिससे वह 'प्रदर्शन प्रोत्साहनों' का लाभ आसानी से उठा सकता है, जबकि एक गरीब राज्य इच्छाशक्ति होने पर भी शीघ्र प्रतिक्रिया देने में सक्षम नहीं हो सकता। इससे विषमता बढ़ सकती है।

अत: 'योगदान' को पुरस्कृत करना लाभों को स्थायी बना सकता है, जब तक कि पिछड़े राज्यों में क्षमता और मानव पूंजी में निवेश द्वारा संतुलन न किया जाये। इसके तीन संभावित असर हो सकते हैं। पहला, बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य खुद को कम दंडित महसूस करेंगे। इससे दक्षिण और पश्चिम के कुछ हिस्सों में नाराजगी कम हो सकती है, जहां तर्क यह रहा है कि हम अधिक योगदान देते हैं, फिर भी हमारी हिस्सेदारी घटती रहती है। दूसरा, पिछड़े राज्यों को मिलने वाली राहत कम हो सकती है। यदि उनमें यह आशंका पैदा हो कि भविष्य के आयोग प्रदर्शन के हिस्से को लगातार बढ़ायेंगे, तो वे विशेष पैकेज, केंद्र प्रायोजित योजनाओं या विवेकाधीन अनुदानों आदि के लिए अधिक दबाव डाल सकते हैं। तीसरा, बातचीत 'जरूरत' से हटकर 'योग्यता' की ओर मुड़ सकती है।

यह राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और सहकारी संघवाद के लिए जोखिम भरा है, क्योंकि गरीब क्षेत्रों को लगेगा कि व्यवस्था अब सुरक्षा कवच प्रदान नहीं करती। कथित उत्तर-दक्षिण तनाव कम होगा या नहीं, यह अन्य राजनीतिक और जनसांख्यिकीय कारकों पर निर्भर करेगा। राजनीतिक शक्ति का केंद्र-उत्तर और पूर्व में है, जबकि आर्थिक भार अधिक दक्षिण में है। यह संरचनात्मक असंतुलन केवल 16वें वित्त आयोग से दूर नहीं होगा। पर संवेदनशीलताओं को देखते हुए फॉर्मूले में कोई भी बदलाव व्यापक चिंता का कारण बन जायेगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वित्त वर्ष के लिए रिजर्व बैंक से 3।1 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरण बजट में शामिल है, जो संघ के राजस्व का लगभग 10 फीसदी है। इसे भी राज्यों से साझा नहीं किया जाता।

सोलहवें वित्त आयोग को 'निरंतरता में परिवर्तन' कहा जा सकता है : वर्टिकल शेयर में स्थिरता, लेकिन हॉरिजेंटल फॉर्मूला में सार्थक संकेत।

नये भारत की नई प्रहार नीति, आतंक के हर रूप से निपटेगा भारत

नीरज कुमार दुबे

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सोमवार को देश की पहली समग्र आतंक विरोधी नीति जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब आतंक के खिलाफ संघर्ष एक संगठित और आक्रामक ढांचे के तहत लड़ा जाएगा। इस नीति का नाम रखा गया है प्रहार। नाम ही संकेत दे रहा है कि यह नीति रक्षात्मक नहीं बल्कि प्रतिघात और प्रतिकार की सोच पर आधारित है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दस्तावेज में साफ कहा गया है कि भारत को सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ साइबर हमलों, ड्रोन के दुरुपयोग और उभरती तकनीकों के जरिये हो रहे हमलों का भी सामना करना पड़ रहा है। दस्तावेज में यह भी उल्लेख है कि अपराधी हैकर और कुछ राष्ट्र लगातार साइबर हमलों के जरिये भारत को निशाना बना रहे हैं। यह खतरा अब केवल बंदूक और बारूद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि की-बोर्ड, कोड और क्रिप्टो वॉलेट तक फैल चुका है।

नीति में यह रेखांकित किया गया है कि भारत जल, थल और नभ तीनों मोर्चों पर आतंकी खतरों से जूझ रहा है। बिजली, रेल, विमानन, बंदरगाह, रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा क्षमता को मजबूत किया गया है ताकि राज्य और गैर राज्य तत्वों की साजिशों को विफल किया जा सके। यह स्पष्ट संकेत है कि अब आतंक के खिलाफ केवल घटनाओं के बाद कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि रणनीतिक तैयारी पहले से की जाएगी।

दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि भारत आतंकवाद को किसी विशेष धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता। लेकिन यह भी उतनी ही स्पष्टता से दर्ज किया गया है कि सीमा पार से प्रायोजित जिहादी आतंकी संगठन और उनके सहयोगी भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहे हैं। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों का नाम लेते हुए नीति में कहा गया है कि ये संगठन स्लीपर सेल के जरिये भारत में हिंसा भड़काने की कोशिश करते रहे हैं।

विशेष चिंता का विषय ड्रोन और रोबोटिक तकनीक का दुरुपयोग है, खासकर पंजाब और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में। हथियार और मादक पदार्थ गिराने से लेकर आतंकी हमलों की साजिश तक, तकनीक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। सोशल मीडिया, एन्क्रिप्शन टूल, डॉर्क वेब और क्रिप्टो वॉलेट के जरिये फंडिंग और प्रचार

का नेटवर्क खड़ा किया जा रहा है। नीति इस डिजिटल युद्ध को पहचानते हुए सीबीआरएनईडी यानी रासायनिक, जैविक, विकिरण, परमाणु, विस्फोटक और डिजिटल सामग्री तक आतंकी पहुंच को रोकने की चुनौती पर जोर देती है।

गृह मंत्रालय ने जांच की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हर स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों को जोड़ने की सिफारिश की है ताकि एफआईआर से लेकर अभियोजन तक केस मजबूत बन सके। यह कदम आतंक के खिलाफ अदालतों में निर्णायक सजा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

कट्टरपंथ के मुद्दे पर भी नीति स्पष्ट है। अक्सर देखने में आता है कि आतंकी संगठन भारतीय युवाओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे मामलों में चरणबद्ध पुलिस प्रतिक्रिया, कानूनी कार्रवाई और पुनर्वास कार्यक्रमों का प्रावधान किया गया है। समुदाय और धार्मिक नेताओं की भूमिका को भी रेखांकित करते हुए कहा गया है कि जागरूकता और संवाद के जरिये युवाओं को भटकने से रोका जाएगा। जेलों में भी डि रेडिकलाइजेशन कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है।

यह नीति केवल घरेलू ढांचा नहीं है। इसमें अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की भी आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि आतंक का नेटवर्क सीमाओं से परे फैला हुआ है। विदेशी संगठन स्थानीय ढांचे और भूगोल का उपयोग कर हमले की साजिश रचते हैं। ऐसे में समन्वित वैश्विक कार्रवाई जरूरी है।

देखा जाये तो प्रहार नीति वस्तुत: उस बदले हुए भारत को दर्शाती है जो अब आतंकवाद को नियति मानकर सहने वाला राष्ट्र नहीं रहा। पिछले एक दशक में मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सीमा पार आतंकवाद का जवाब केवल कूटनीतिक नोटिस से नहीं बल्कि निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब यह नीति उस सोच को संस्थागत रूप दे रही है।

भारत की प्रहार नीति का सामरिक महत्व अत्यंत गहरा है। यह स्पष्ट संदेश देती है कि भारत बहु आयामी युद्ध को समझता है। आतंक अब केवल सीमा पर घुसपैठ नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, वित्तीय नेटवर्क और वैचारिक प्रचार के जरिये भी फैलाया जाता है। प्रहार इन सभी मोर्चों पर एकीकृत प्रतिक्रिया का ढांचा प्रस्तुत करता है। साथ ही यह नीति रक्षात्मक मानसिकता से बाहर निकलकर सक्रिय प्रतिरोध और पूर्व तैयारी की रणनीति अपनाती है। इसके अलावा, यह कानून, तकनीक और समाज तीनों को एक साथ जोड़ती है।

सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की नीति ने स्पष्ट कर दिया है कि अब धैर्य की भी सीमा है। कश्मीर में आतंकी ढांचे को तोड़ने, फंडिंग पर नकेल कसने और अलगाववादी नेटवर्क को ध्वस्त करने के कदमों ने जमीन पर असर दिखाया है। प्रहार उसी क्रम का अगला चरण है जहां आतंक के हर स्वरूप को चिन्हित कर व्यवस्थित ढंग से कुचला जाएगा।

जो लोग आतंक के खिलाफ कठोर नीति को लेकर संशय जताते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा भावनात्मक उदारता से नहीं बल्कि कठोर निर्णयों से सुरक्षित होती है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी धर्म को आतंक से नहीं जोड़ता, लेकिन आतंक के नाम पर देश को अस्थिर करने की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देगा।

बहरहाल, प्रहार नीति एक संदेश है कि नया भारत हमले का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे की पहचान कर पहले ही प्रहार करता है। यही रणनीतिक परिपक्वता किसी भी उभरती शक्ति की पहचान होती है। आतंक के खिलाफ यह संगठित, आक्रामक और समन्वित दृष्टिकोण आने वाले समय में भारत की सुरक्षा संरचना को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी फ्रीबीज बनाम रोजगार की बहस तेज

कांतिलाल मांडोत

देश में मुफ्त योजनाओं को लेकर चल रही बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकारें सुबह से शाम तक लोगों को मुफ्त राशन गैस और बिजली देती रहेंगी तो लोग काम क्यों करेंगे। इससे काम करने की आदत खत्म हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सरकारों को रोजगार सृजन पर ध्यान देना चाहिए ताकि लोग सम्मानपूर्वक अपनी आजीविका कमा सकें। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। कंपनी ने ऐसे प्रावधान को चुनौती दी है जिसमें उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति देखे बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव रखा गया है। अदालत ने सवाल उठाया कि जो लोग भुगतान करने में सक्षम हैं और जो नहीं हैं उनके बीच बिना कोई अंतर किए मुफ्त सुविधा देना क्या तुष्टीकरण की नीति नहीं है। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। अदालत ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व घाटे से जूझ रहे हैं और इसके बावजूद विकास कार्यों की बजाय मुफ्त घोषणाओं पर जोर दिया जा रहा है। न्यायालय ने यह भी पूछा कि चुनावों के आसपास ऐसी योजनाओं की घोषणा क्यों की जाती है और क्या इससे वित्तीय अनुशासन प्रभावित नहीं होता। अदालत की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब राज्यों की वित्तीय स्थिति पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार 19 राज्यों की कुल सब्सिडी का लगभग 53 प्रतिशत हिस्सा केवल बिजली सब्सिडी पर खर्च होता है। वर्ष 2024 25 में राज्यों का संयुक्त राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत रहा है। मार्च 2025 तक राज्यों पर कुल कर्ज जीडीपी का 27.5 प्रतिशत रहा और अगले वर्ष इसके 29 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। ब्याज भुगतान की दर भी राजस्व वृद्धि से तेज गति से बढ़ रही है। तमिलनाडु में घरेलू उपभोक्ताओं को हर दो महीने में लगभग 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। पंजाब में बड़ी मात्रा में बिजली सब्सिडी दी जा रही है। दिल्ली में सीमित यूनिट तक बिजली और पानी मुफ्त या रियायती दर पर उपलब्ध है। बिहार और हिमाचल प्रदेश में भी घरेलू उपभोक्ताओं को निर्धारित सीमा तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। कई राज्यों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाती है। इन योजनाओं का उद्देश्य राहत देना है परंतु इनके दीर्घकालिक आर्थिक प्रभावों को लेकर बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी मुफ्त राशन और अन्य रियायतों पर चिंता जताई थी। अदालत ने कहा था कि अनिश्चितकाल तक मुफ्त वितरण से लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के बजाय निर्भरता बढ़ सकती है। हालांकि न्यायालय ने यह भी माना कि गरीबों और जरूरतमंदों को राहत देना कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारी है। प्रश्न यह है कि सहायता लक्षित होनी चाहिए या सार्वभौमिक। भारत में मुफ्त योजनाओं का इतिहास नया नहीं है। 1950 और 1960 के दशक में मद्रास राज्य में कामराज ने मुफ्त शिक्षा और मध्याह्न भोजन की शुरुआत की थी। बाद के दशकों में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में सस्ती दर पर चावल वितरण की योजनाएं आईं। समय के साथ मुफ्त टीवी साइकिल लैपटॉप और घरेलू उपकरण तक चुनावी वादों का हिस्सा बने। 2015 के बाद दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता जैसी योजनाएं भी विभिन्न राज्यों में लागू हुईं। समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक असमानता वाले देश में कमजोर वर्गों को बुनियादी सुविधाएं देना सरकार का दायित्व है। शिक्षा स्वास्थ्य भोजन और ऊर्जा जैसी आवश्यक सेवाओं पर राहत से जीवन स्तर सुधरता है और मानव संसाधन मजबूत होता है। आलोचकों का कहना है कि यदि योजनाएं वित्तीय क्षमता से अधिक हों तो विकास परियोजनाओं पर असर पड़ता है और कर्ज का बोझ बढ़ता है। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भार पड़ सकता है।

अब अपनी हॉबी को ही बना सकते हैं करियर ऑप्शन

आज के समय में जॉब करना आसान नहीं रह गया है। यह काम तब और मुश्किल हो जाता है, जब किसी का प्रोफेशन और हॉबी अलग-अलग हो। जिसके कारण आजकल कई लोग जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन वे उन जॉब्स से खुश नहीं हैं। पैसा कमाने के लिए जॉब करना और अपने पैशन को फॉलो करके उसमें आगे जाना दोनों बहुत अलग बात हैं। फिर चाहे उसमे पैसे थोड़े कम क्यों न हो।

फोटोग्राफी, राइटिंग, म्यूजिक, डांस, सिंगिंग, कुकिंग, पेंटिंग समेत कई ऐसी हॉबी होती हैं, जिन्हे आप फुल टाइम करियर में बदल सकते हैं। सोचिये जो काम आपको सबसे ज्यादा पसंद है और आपकी हॉबी है, उसे आप अलग से समय निकाल कर करते हैं, अगर इसी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लें तो कितना अच्छा रहेगा। अगर आप भी अपनी हॉबी को करियर का रूप देना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए 7 टिप्स को फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले रिसर्च करें

अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए सबसे पहले जो काम आपको करना है वो है रिसर्च। किसी भी हॉबी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता लगाना है कि क्या आपकी हॉबी फुल टाइम करियर बना सकती है या नहीं। उसमें जॉब और करियर के क्या अवसर हैं और उस क्षेत्र में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने अनुभव की जरूरत पड़ती है।

सही फीडबैक लें

कोई भी व्यक्ति अपने काम को जज नहीं कर सकता और न ही आपका परिवार या दोस्त आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। किसी भी काम को शुरू करने से पहले गाइडेंस के लिए जरूरत होती है एक अनुभवी प्रोफेशनल की जो आपका मेंटर बने। हमेशा याद रखें कि काम शुरू करने से पहले अपनी हॉबी के बारे में अपने मेंटर से ईमानदार फीडबैक लेना बिल्कुल ना भूलें।

शुरू से शुरुआत करें

यह बात पहले ही अपने मन में बैठा लें कि जब आप कोई करियर स्विच करेंगे तो हो सकता है कि आपको नीचे से ही शुरू करना पड़े। आप अपनी जॉब में फिलहाल ऊंची पोस्ट पर हों, लेकिन आपको नये करियर में नीचे से ही शुरू करना होगा। इसलिए अपनी तैयारी पहले से ही पूरी कर लें।

पुरानी स्किल्स का इस्तेमाल

आपके पुराने और नये करियर में भले ही कोई समानताएं न हों। लेकिन फिर भी हर जगह से हम कुछ न कुछ स्किल्स तो सीखने को मिलती ही हैं। ऐसी कई स्किल होती हैं, जो हर फील्ड में काम आती हैं। जैसे अगर आप किसी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पेंटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्किल यहां भी काम आएगी। इसलिए ध्यान रखें कि सभी स्किल का इस्तेमाल अपने नये करियर में करें।

अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बनें

अपनी हॉबी में करियर बनाने से पहले आप उस फील्ड से जुड़े लोगों से संपर्क बनाएं। अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाएं, एक अच्छा नेटवर्क बनाएं। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आपको उस फील्ड में सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करें।

अपने काम को मोनेटाइज करें

प्रूफ ऑफ कंसेप्ट एक बिजनेस टर्म है जिसका इस्तेमाल उन उद्यमियों के द्वारा किया जाता है जो फंडिंग की तलाश में होते हैं। आपको भी अपने लिए फंडिंग का इंतजाम करना चाहिए। क्योंकि किसी भी काम के लिए आर्थिक सुविधा बहुत जरूरी है। अगर वह नहीं रहेगा तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अपने काम से पैसे कमाने की कोशिश करें। आप चाहे तो आपकी स्किल को ऑनलाइन सिखा सकते हैं, एक्सपर्ट लेक्चर ले सकते हैं। या फिर खुद की वर्कशॉप भी लगा सकते हैं।

इस तरह बदले अपने पैशन को प्रोफेशन में

जब आपके मन में अपने पैशन को प्रोफेशन बनाने का विचार आए तो सबसे पहले अपने सभी हॉबी की लिस्ट बनाएं। मान लीजिये आपकी तीन हॉबी हैं। आपको लिखने का शौक हैं, फोटोग्राफी और पेंटिंग का भी शौक है। अब एक- एक हॉबी पर विचार कीजिए और उसके साथ कुछ दिन जी कर देखें। इससे आपको अपने आप ही मालूम हो जायेगा कि किस काम को लेकर आप ज्यादा बेहतर हैं और वह कार्य करते हुए आपको ज्यादा खुशी मिलती है।

सफलता के लिए हमेशा याद रखें...

किसी भी कार्य की सफलता के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए। कार्य को प्रारम्भ करने के पीछे हमारा भाव क्या है। हम क्या करना चाहते हैं इसका महत्व है। सफलता के लिए भगवान का सुमिरन कर कार्य करें। भगवान का ध्यान कर किए जाने वाले कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। केवल परिश्रम से कुछ नहीं होता। कुछ लोग भगवान की असीम कृपा से कम परिश्रम में भी सफलता की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। संतों ने सफलता के 3 मंत्र बताए। पहला भगवान का स्मरण, दूसरा धैर्य तथा तीसरा परमार्थ की भावना जुड़ी होनी चाहिए।

प्रत्येक मंदिर बाहर से स्वच्छ होना चाहिए और भीतर से पवित्र होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति भी बाहर से स्वच्छ और भीतर से पवित्र होना चाहिए। फिर कोई लम्बी साधना करने की जरूरत नहीं। मां त्रिस्तरीय काम करती है। सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका परिपालन और उसका संघार करती है। अम्बा के 3 स्तर हैं, स्त्री शरीर अम्बा का ही अंश है। ऐसा मानकर उसका 3 स्तर पर सम्मान करना चाहिए। कन्या का सम्मान, धर्मपत्नी का सम्मान और मां का सम्मान। आनंद की अंतिम सीमा आंसू हैं। हम सबका जीवन फल होना चाहिए प्रेम। सत्य शायद हम चूक जाएं। करुणा छूट जाए लेकिन प्रेम बना रहे। यह जीवन का फल है।

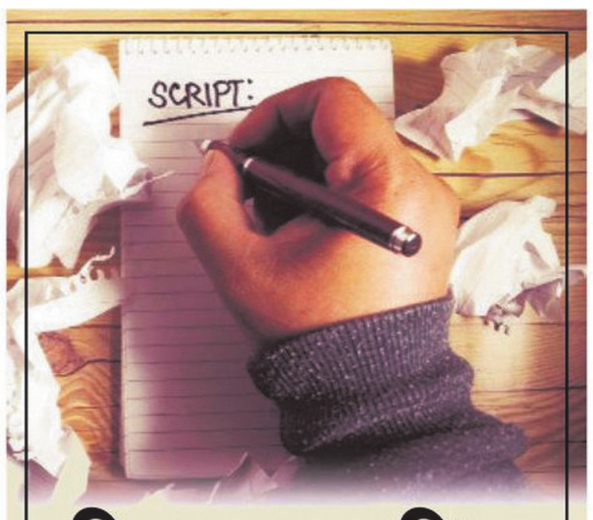

स्क्रिप्ट राइटिंग में करियर

यदि आप लेखन में दक्षता रखते हैं और आपको किताबें पढने में भी गहरी रुचि है तो स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर आप अपने शौक को करियर का रूप भी दे सकते हैं। जो युवा लिखने-पढने के साथ मानवीय संवेदनाओं को पकड़ कर अभिव्यक्त करने की क्षमता रखते हैं उनके लिए भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।

कार्यक्षेत्र

विज्ञापनों के लिए स्क्रिप्ट राइटर्स की सेवाएं विशेष तौर पर ली जाती हैं। अक्सर विज्ञापनों में ऐसे शब्दों या पंक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाती हैं। ये सब स्क्रिप्ट राइटर के दिमाग की ही उपज होते हैं। ऐसी रोचक बातों को जिंगल्स कहा जाता है।

बेशक स्क्रिप्ट राइटर का काम सिर्फ जिंगल लिखना ही नहीं होता बल्कि और कई चीजें हैं जो स्क्रिप्ट राइटर करते हैं लेकिन अधिकतर की शुरूआत जिंगल्स से ही होती है। जाहिर है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कहानियां और कविताएं लिखने से कुछ अलग होता है क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखी गई हर बात का फिल्मांकन किया जाता है इसीलिए लेखक को यह सोचकर लिखना पड़ता है कि उसके द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं देखी जाएगी।

कौशल

इसमें क्षेत्र में करियर बनाने के लिए छात्रों में रचनात्मकता का होना आवश्यक है। कम शब्दों में आपको उत्पादों की विशेषताओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना होता है। विज्ञापनों के लिए ऐसी जिंगल्स की रचना करनी पड़ती है कि सुनते या पढ़ते ही वह ग्राहक के जेहन में आ जाए। वैसे कोई डिग्री कोर्स तो नहीं होता पर ये जर्नलिज्म के अंतर्गत आता है।

कल तक विज्ञापन ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बनाए जाते थे लेकिन आज जो विज्ञापन आ रहे हैं वे ग्राहकों के संतोष के साथ उसकी खुशी और मनोरंजन को भी महत्व दे रहे हैं। मानवीय भावनात्मक पक्षों को छूते विज्ञापन न सिर्फ देर तक याद रहते हैं बल्कि मन पर भी गहरा असर छोड़ते हैं।

जिस भी भाषा में आप स्क्रिप्ट राइटिंग करना चाहते हैं उसका गहन ज्ञान आपको होना चाहिए। आपको अधिक से अधिक पुस्तकों को भी पढना चाहिए ताकि आपको विभिन्न लेखकों की शैली की जानकारी भी प्राप्त हो सके। साथ ही फिल्मों तथा धारावाहिकों की स्क्रिप्ट पर गौर करने की आदत भी डाल लें। इसके बाद आप स्क्रिप्ट लेखन में हाथ आजमाएं।

योग्यता

स्क्रिप्ट राइटिंग में सबसे अहम जरूरत रचनात्मकता की होती है जो पूर्णत- व्यक्ति की विश्लेषण और कल्पना क्षमता पर आधारित होती है लेकिन फिर भी इसके लिए पत्रकारिता का कोर्स कर लिया जाए तो बेहतर होता है। किसी भी विषय में 12वीं कक्षा पास करने के बाद पत्रकारिता में ग्रैजुएशन कर सकते हैं। जो छात्र ग्रैजुएशन कर चुके हैं वे किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पत्रकारिता में एम.ए. भी कर सकते हैं।

प्रमुख संस्थान

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
एमिटी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली
इंडियन इंस्टी. आफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, मध्य प्रदेश
माखन लाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

लाभदायक करियर इमेज कंसल्टिंग

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरैंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के ढंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टैंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमैंट, पॉलिसी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनैस इंस्टी. भारत में इमेज कंसल्टैंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनैस प्रोग्राम संबंधी अनोखे पेशेवर कोर्स करवाता है। इस संस्थान की डायरैक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टैंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान की डायरैक्टर हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 2009 में की। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफैशनल इंटरनैशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टैंट बन गईं। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, ''80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कौशल एक इमेज कंसल्टैंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।'' उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

पत्राचार शिक्षा से बदलती युवाओं की तकदीर

आज सभी विषयों में ग्रैजुएशन तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टीफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है। अधिकतर पत्राचार पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें सभी विषय-विधाओं के 10+2 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। उपग्रह संचार, लो पावर ट्रांसमीटर्स की सहायता एवं सूचना सुपर-हाइवेज के माध्यम से देश भर में शिक्षा का प्रसार हो रहा है।

देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, सेवारत व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं।

अधिकांश विश्वविद्यालय मुद्रित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए उत्साहित हूं : मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा पर इजरायल के लिए रवाना हो गए। रवानगी से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने भारत और इजरायल के बीच के स्थायी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने इस यात्रा को दोनों देशों के बीच मजबूत और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी का एक नया अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बातचीत को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर इजराइल के लिए रवाना हुए। इजराइल यात्रा के लिए रवाना होने से पहले मोदी ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनकी यह यात्रा भारत और इजराइल के बीच ''स्थायी संबंधों'' को और मजबूत करेगी, रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी तथा एक सशक्त, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य के लिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी।

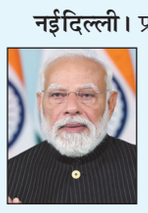

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेहरू पर लगाया बड़ा आरोप

पटना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नेहरू-गांधी परिवार पर हमला बोला है। बुधवार सुबह उन्होंने इसे 'समझौता मिशन' की राजनीति बताते हुए आरोप लगाया कि परिवार के हितों को देशहित से ऊपर रखा गया। नवीन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में बिना किसी प्रतिफल के तिब्बत में भारत के अधिकार चीन को सौंप दिए। उन्होंने कहा कि नेहरू ने कभी 45 करोड़ भारतीयों को अपनी 'जिम्मेदारी' बताया था, लेकिन उनके फैसलों ने राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाया। भाजपा अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उस समय रक्षा सौदों का इस्तेमाल निजी हितों के लिए किया गया। उन्होंने दावा किया कि रक्षा सेवाओं के माध्यम से निजी बैंक खातों को भरने का काम हुआ। नवीन ने राहुल गांधी को 'विदेशी शक्तियों की कठपुतली' बताते हुए कहा कि कांग्रेस का चुनावी इतिहास कथित तौर पर सीआईए फंडिंग से प्रभावित रहा है।

बारामती विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगी सुनेत्रा पवार

मुंबई। महाराष्ट्र की राजनीति में एक युगांतरकारी बदलाव होने जा रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने दिवंगत नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद खाली हुए नेतृत्व के शून्य को भरने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को हुई पार्टी की अहम बैठक में सुनेत्रा पवार को बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है, साथ ही उन्हें पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि यह फैसला मंगलवार को हुई पार्टी की एक अहम मीटिंग में लिया गया। उसी मीटिंग में, पार्टी लीडरशिप ने पार्थ पवार के राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन को भी फाइनल कर दिया। वह अपर हाउस में अपनी मां सुनेत्रा पवार की जगह लेंगे। सुनेत्रा अपने पति की मौत के बाद महाराष्ट्र में महायुति सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनी हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की सात खाली सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होने हैं।

सुप्रीम कोर्ट एनसीईआरटी किताब विवाद पर सख्त

नईदिल्ली। देश की न्यायिक व्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण विवाद उस समय खड़ा हो गया जब आठवीं कक्षा की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की नयी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका के सामने मौजूद चुनौतियों के रूप में भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों की बड़ी संख्या और न्यायाधीशों की कमी का उल्लेख किया गया। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय ने गंभीर आपत्ति जताते हुए स्वत: संज्ञान लिया और कहा कि न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने की किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की सुनियोजित साजिश प्रतीत होती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ''मैं किसी को भी संस्था को बदनाम करने की अनुमति नहीं दूंगा। कानून अपना काम करेगा।'' उन्होंने कहा, ''संस्था के प्रमुख के रूप में मैंने अपना कर्तव्य निभाया है और संज्ञान लिया है।

2027 में 50 फीसदी सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेगी बसपा!

कानपुर। यूजीसी प्रकरण के बाद विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से ब्राह्मण बिरादरी का दखल बढ़ गया है जिससे राजनीतिक दलों खासकर विपक्षी दलों की ओर से इस पर विशेष अमल किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी इस पर पकड़ बनाने में सबसे आगे दिखाई दे रही है। पार्टी प्रमुख मायावती के निर्देशन में पदाधिकारियों की ओर से इस फार्मूले पर काम भी शुरू कर दिया गया है। तय किया गया है कि यूपी में बसपा 40 से 50 सीटों पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतार सकती है। जालौन के माधौगढ़ सीट से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक विधानसभा सीट पर चार-चार दावेदारों का पैनल बनाकर उनको कसौटी पर परखा जा रहा है। इन्हीं में से एक को पहले विधानसभा क्षेत्र प्रभारी और बाद में प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। प्रभारी बनाने के बाद उसी को प्रत्याशी घोषित करने के लिए बसपा उसी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा सम्मेलन करेगी।

शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भाजपा-कांग्रेस में घमासान

पीयूष गोयल ने नेहरू-बोफोर्स की दिलाई याद

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को एआई शिखर सम्मेलन में भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोप वैश्विक मंच पर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास हैं। गोयल ने एक्स पर कई पोस्ट लिखकर समझौतावादी कांग्रेस हैशटैग का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी पर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली अपनी पारिवारिक विरासत को जारी रखने का आरोप लगाया। उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकारों के दौरान लिए गए फैसलों का हवाला दिया, जिनमें जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सीट के कथित प्रस्ताव पर भारत का रुख, राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान बोफोर्स घोटाला और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कच्चातीवू समझौता शामिल हैं।

गोयल ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जब बिना शर्ट पहने पुरुषों को एआई शिखर सम्मेलन में भेजकर भारत को वैश्विक मंच पर अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह भारत की छवि और हितों से समझौता करने की उनकी पारिवारिक विरासत का ही विस्तार है। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी राहुल गांधी की 2024 में हुई अमेरिका यात्रा की आलोचना की। जोशी ने कहा कि लोकतंत्र पर चर्चा

के रूप में प्रस्तुत की गई इस यात्रा में इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़े कार्यकर्ताओं और जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित नेटवर्क से कथित तौर पर जुड़े व्यक्तियों के साथ हुई मुलाकातों के कारण चिंताएं बढ़ गईं। उन्होंने यह भी दावा किया कि कतर ने कथित तौर पर इनमें से कुछ मुलाकातों में सहायक भूमिका निभाई।

जोशी ने कहा कि जब विदेशों में होने वाली मुलाकातों से संवाद और संदिग्ध नेटवर्किंग के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है, तो नागरिकों का स्पष्टता की मांग करना जायज़ है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि राष्ट्रीय हितों से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद ज़रूरी हैं। जोशी ने एक्स पर लिखा कि अब 2024 की बात करें, तो राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा को लोकतंत्र पर बातचीत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन असलियत कुछ और ही बयां करती है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल से जुड़े कार्यकर्ताओं और सोरोस द्वारा वित्तपोषित नेटवर्कों से जुड़े व्यक्तियों के साथ हुई मुलाकातें, जिनमें कतर की भूमिका कथित तौर पर मध्यस्थ की रही, इरादों और तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। जब विदेशों में होने वाली मुलाकातों से संवाद और संदिग्ध नेटवर्किंग के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है, तो नागरिकों का यह सवाल पूछना जायज़ है- क्या यह कूटनीतिक संपर्क है या कुछ और भी चिंताजनक? राष्ट्रीय हितों की बात आने पर पारदर्शिता और जवाबदेही चुनिंदा नहीं हो सकती।

पिछले सप्ताह, भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने एआई इम्पैक्ट समिट की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री पर समझौते का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान, पार्टी कार्यकर्ताओं ने असहमति जताने के लिए अपनी शर्ट उतार दीं। एक बयान में, भारतीय युवा कांग्रेस ने कहा कि उसके कार्यकर्ता एक ऐसे समझौतावादी प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने एआई समिट में देश की पहचान का सौदा किया है। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

पीएम नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे पर प्रियंका गांधी का तंज

उम्मीद है गाजा में नरसंहार का मुद्दा उठाएंगे प्रधानमंत्री

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय ऐतिहासिक इजरायल यात्रा शुरू होने से पहले ही देश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने बुधवार को पीएम मोदी से तंज कसते हुए आग्रह किया है कि वे इजरायली संसद (नेसेट) को संबोधित करते हुए गाजा के हालातों पर अपनी आवाज उठाएं। कांग्रेस नेता ने भारत की विदेश नीति और नैतिक मूल्यों को याद दिलाते हुए कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है।

प्रियंका गांधी वाद्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इजराइली संसद को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के 'नरसंहार' का उल्लेख करेंगे तथा उनके लिए न्याय की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को दो दिवसीय यात्रा पर इजराइल जा रहे हैं जहां वह इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के साथ ही इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करेंगे।

प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, ''मुझे आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी अपनी आगामी इजराइल यात्रा पर नेसेट को संबोधित करते हुए गाजा में हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के नरसंहार का उल्लेख करेंगे और उनके लिए न्याय की मांग करेंगे।'' उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत अपने पूरे इतिहास में जो सही है, उसके लिए खड़ा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ''हमें दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना होगा।

कांग्रेस नेता ने भारत की विदेश नीति और नैतिक मूल्यों को याद दिलाते हुए कहा कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहा है। उन्होंने जोर दिया कि- भारत का इतिहास सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहने का रहा है। भारत को पूरी दुनिया को सत्य, शांति और न्याय की रोशनी दिखाते रहना चाहिए।

नेतन्याहू से दोस्ती, देश से धोखा : कांग्रेस

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इजराइल दौरे से पहले बुधवार को आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना कर रही है तो प्रधानमंत्री मोदी वहां ''नैतिक कायरता'' का परिचय देने जा रहे हैं।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, ''20 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू गाजा में थे और उन्होंने वहां संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल की भारतीय टुकड़ी से मुलाकात की थी। 29 नवंबर 1981 को भारत ने फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रदर्शित करते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। 18 नवंबर 1988 को भारत ने औपचारिक रूप से फलस्तीन राष्ट्र को मान्यता दी।'' उन्होंने कहा, ''वह एक अलग युग था। अब भारतीय प्रधानमंत्री बेशर्मी से इजराइल के प्रधानमंत्री को गले लगा रहे हैं, जिन्होंने गाजा को मलबे और धूल में बदल दिया है और जो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के विस्तार की योजना बना रहे हैं।'' रमेश ने आरोप लगाया कि जब पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के प्रिय मित्र नेतन्याहू की आलोचना कर रही है, तो मोदी ''नैतिक कायरता'' प्रदर्शित करने जा रहे हैं।

प्रियंका गांधी के गाजा वाले बयान पर भाजपा का तीखा पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय इजराइल यात्रा को लेकर देश में सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा गाजा में नरसंहार का मुद्दा उठाए जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उन पर बेहद कड़ा हमला बोला है। भाजपा ने प्रियंका गांधी को ''भारतीय राजनीति की महिला गजनी'' करार देते हुए उन पर सुविधाजनक आक्रोश व्यक्त करने का आरोप लगाया है। 'महिला गजनी' का यह संदर्भ 2008 की हिंदी फिल्म 'गजनी' के एक पात्र से प्रेरित है जिसकी याददाश्त बार-बार चली जाती है और उसे सिर्फ कुछ देर ही बातें याद रहती हैं। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी को गाजा में मानवीय संकट दिखता है लेकिन वह इजराइल में सात अक्टूबर के हमलों को भूल गई हैं। प्रियंका की टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने 'एक्स' पर लिखा, ''भारतीय राजनीति की 'महिला गजनी' वापस आ गई हैं!'' भाटिया ने कांग्रेस नेता की एक पुरानी तस्वीर साझा की जिसमें वह 'फलस्तीन' लिखा हुआ बैग लिए खड़ी हैं। उन्होंने कहा, ''संसद में 'फलस्तीन' लिखा हुआ बैग ले जाना तो आसान है लेकिन सात अक्टूबर को 1,200 से अधिक निर्दोष लोगों के नरसंहार, महिलाओं के अपहरण और बलात्कार की निंदा करने का नैतिक साहस दिखाना प्रियंका गांधी के लिए स्पष्ट रूप से बहुत मुश्किल है।'' भाटिया ने कहा कि ऐसे कृत्यों की निंदा करने के लिए बहुत नैतिक साहस की आवश्यकता होती है और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना पड़ता है। उन्होंने कहा, ''आप भले ही गांधी उपनाम का इस्तेमाल करती हों, लेकिन आपमें दृढ़ विश्वास और साहस की कमी है।'' मोदी की इजराइल यात्रा बुधवार से शुरू हो रही है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा और व्यापार सहयोग को मजबूत करना है। नौ वर्षों में यह उनकी इजराइल की दूसरी यात्रा है।

खेल
प्रमुख समाचार

सुपर-8 में आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला

चेन्नई। सुपर-8 में दक्षिण अफ्रीका से 76 रन की करारी हार के बाद भारतीय टीम में मंथन तेज हो गया है। भारत को अब सुपर-8 राउंड में 26 फरवरी को जिम्बाब्वे से चेन्नई में और एक मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज से खेलना है। अब टीम इंडिया के सामने जिम्बाब्वे और वेस्टइंडीज के खिलाफ 'करो या मरो' के मुकाबले हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या टीम मैनेजमेंट संयोजन में बदलाव करेगा या खिलाड़ियों पर भरोसा बनाए रखेगा। सुपर-8 की हार ने टीम इंडिया को आत्ममंथन के दौर में ला खड़ा किया है। बल्लेबाजों की खराब फॉर्म और संतुलन की कमी को देखते हुए बदलाव की संभावना प्रबल है। हालांकि अंतिम फैसला मैच से ठीक पहले लिया जाएगा। आने वाले दो मुकाबले भारत के लिए परीक्षा की घड़ी साबित होंगे।

टीम मैनेजमेंट अब कम से कम एक आउट-ऑफ-फॉर्म बल्लेबाज को बाहर करने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। मुख्य कोच गौतम गंभीर के सहयोगी कोच रेयान टेन डेशकाटे और बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने संकेत दिए हैं कि अगले मैच में प्लेइंग-11 में बदलाव संभव है। रिंकू सिंह के भी खेलने पर सस्पेंस है, क्योंकि वह मंगलवार को परिवार में आपात की स्थिति में घर लौट गए। वह टीम से कब जुड़ेंगे, इस पर अपडेट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा सुंदर को बाहर कर अक्षर पटेल की वापसी हो सकती है।

बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने साफ कहा, अगर हेड कोच और टीम मैनेजमेंट को लगता है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए, तो हम बदलाव करेंगे। अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सोचना होगा कि क्या बदलें और कैसे बदलें। उन्होंने आगे कहा, हमें यह तय करना होगा कि क्या उसी संयोजन के साथ जाएं या कुछ नया आजमाएं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 54 अंक चढ़ा निफ्टी 25482 पर बंद

नईदिल्ली। एशियाई बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार बुधवार (25 फरवरी) को सपाट रुख के साथ बंद हुए। शुरूआती कारोबार में शानदार मजबूती के बाद कारोबार के आखिरी घंटे में बाजार ने बढ़त गंवा दी। आईटी शेयरों में तेजी के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी गिरावट से बाजार सपाट रुख के साथ बंद हुआ। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स मजबूती के साथ 82,530 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 82,957 अंक चढ़ गया था। अंत में 50.15 अंक या 0.06 प्रतिशत की बढ़त लेकर 82,276.07 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी बढ़त के साथ 25,512 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान इसने 25,652 अंक का इंट्रा-डे हाई छुआ लेकिन अंत में 57.85 अंक या 0.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,482 पर बंद हुआ।

सीएम योगी के जापान दौरे में मिले मेगा निवेश प्रस्ताव

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन औद्योगिक निवेश को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विभिन्न जापानी कंपनियों के साथ लगभग 11 हजार करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। जिन कंपनियों के साथ करार हुआ है उनमें कुबोता कारपोरेशन, मिंडा कारपोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएंडओ ग्रुप, फूजी जैपनीज जेवी और फूजीसिल्वरटेक कंक्रीट प्रा. लि. शामिल हैं। ये समझौते कृषि यंत्र निर्माण, औद्योगिक मशीनरी निर्माण, जल और पर्यावरण अवसंरचना समाधान, ऑटोमोबाइल, औद्योगिक प्रिंटिंग एवं ग्राफिक्स, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट जैसे विविध क्षेत्रों से जुड़े हैं। इससे विनिर्माण क्षमता के विस्तार और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

अमेरिका ने भारतीय सोलर उद्योग पर लगाया आयात शुल्क

वाशिंगटन। भारतीय सोलर उद्योग को अमेरिकी बाजार में बड़ा झटका लगा है। यूनाईटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने भारत से आयात होने वाले सोलर सेल और सोलर पैनल पर भारी काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) लगाने की घोषणा की है। यह कदम भारत के अलावा इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले सोलर उत्पादों पर भी लागू होगा। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि इन देशों की कंपनियों को सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है, जिससे अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा में नुकसान उठाना पड़ता है। जारी फैक्ट शीट के अनुसार भारत पर 125.87 प्रतिशत काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई गई है। इंडोनेशिया पर 104.38 प्रतिशत और लाओस पर 80.67 प्रतिशत ड्यूटी निर्धारित की गई है। यह फैसला अमेरिकी सोलर निर्माताओं के एक समूह द्वारा दायर याचिका के बाद लिया गया है।

टेक और एआई बदल रहे भारत में प्रतिस्पर्धा का माहौल

नईदिल्ली। बड़ी टेक कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते विस्तार ने भारत में प्रतिस्पर्धा के माहौल को बदल दिया है। इसी वजह से अब इन पर नियामक (रेगुलेटर) की नजर और कड़ी हो गई है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की चेयरपर्सन रवनीत कौर ने यह बात कही। कौर ने एक समिट में कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल बाजार और बड़ी टेक कंपनियां सीसीआई के लिए खास फोकस का क्षेत्र बन गई हैं। उन्होंने बताया कि भारत में डिजिटल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इससे प्रतिस्पर्धा से जुड़े नए सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी टेक कंपनियों से कुछ जोखिम भी पैदा होते हैं। अपने ही प्रोडक्ट को प्राथमिकता देना, एक सेवा के साथ दूसरी सेवा को जबरन जोड़ना, प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचाने वाले समझौते और उपभोक्ताओं पर अनुचित शर्तें थोपना।

पीपीपी मॉडल का पुनर्जीवन: भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति देने के लिए रीसेट जरूरी

विनायक चटर्जी

भारत का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल एक स्पष्ट सबक देता है। जब इन परियोजनाओं की डिजाइन संतुलित होती है और इनका क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जाता है तब वे बुनियादी ढांचा के विकास को नई गति दे सकती हैं लेकिन यदि इनकी संरचना त्रुटिपूर्ण हो तो वही परियोजनाएं वर्षों तक वृद्धि की रफ्तार को बढ़ने नहीं देतीं।

वर्ष 2000 के दशक के बुनियादी ढांचा में उछाल के दौरान विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों, बिजली, बंदरगाहों और हवाईअड्डों के क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2007-12) के दौरान बुनियादी ढांचा व्यय का लगभग 37 फीसदी हिस्सा निजी निवेश से आया। वर्ष 2009 से 2013 के बीच, नए राष्ट्रीय राजमार्गों का लगभग 60 फीसदी यानी 6,300 किलोमीटर से अधिक सड़कें, टोल आधारित 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर' (बीओटी) मॉडल के तहत पीपीपी के माध्यम से तैयार की गईं।

हालांकि यह रफ्तार अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। 2010 के दशक के मध्य तक अनेक पीपीपी परियोजनाएं धीमी पड़ गईं, वित्तीय संकट में फंस गईं या भुगतान चूक वाली स्थिति में पहुंच गईं। इसके अलावा डेवलपर को भूमि अधिग्रहण और मंजूरी मिलने में देरी, यातायात वृद्धि में कमी, अत्यधिक ऋण भार और बढ़ती लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई कंपनियों ने बहुत कम टोल दरों का अनुमान लगाकर आक्रामक बोली लगाई। इससे वे परियोजनाएं तो जीत गईं लेकिन बाद में कम आमदनी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और उनकी बैलेंसशीट पर

बुरा असर पड़ा।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें जोखिम का बंटवारा संतुलित नहीं था। अत्यधिक जोखिम वाले पहलू निजी क्षेत्र पर डाल दिए गए और अनुबंधों को लगभग अपरिवर्तनीय माना गया। औपचारिक तौर पर दोबारा विचार या दोबारा समझौते की व्यवस्था न होने के कारण मूल रूप से व्यवहारिक परियोजनाएं भी अटक गईं। जैसा कि केलकर समिति (2015) ने भी चेतावनी दी थी, 'जोखिम का अक्षम और असमान वितरण पीपीपी परियोजनाओं की विफलता का एक प्रमुख कारण बन सकता है।'

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में एक बार फिर अवसंरचना को विकास का प्रमुख इंजन बताते हुए परिवहन, शहरी विकास, आवास, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय फंडिंग के क्षेत्रों में अनेक पहल की घोषणा की गई है। लेकिन इसमें भारत के बुनियादी ढांचा रणनीति के सामने खड़े सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्न को नजरअंदाज किया गया है कि देश पीपीपी को बुनियादी ढांचा विकास के केंद्रीय स्तंभ के रूप में कैसे फिर से बहाल करेगा? यह चूक वैचारिक नहीं बल्कि संरचनात्मक है। सार्वजनिक वित्त की अपनी सीमाएं हैं। राज्य सरकारें और शहर पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं। शहरी परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, बिजली और लॉजिस्टिक्स जैसी बुनियादी ढांचा आवश्यकताएं बजटीय क्षमता से कहीं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में पीपीपी कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। फिर भी हाल के वर्षों में निजी भागीदारी अपने पूर्व उच्च स्तर से घटकर लगभग 20-22 फीसदी पर आ गई है (आर्थिक सर्वेक्षण 2024)। अगर इस रुझान को नहीं बदला गया तब भारत की बुनियादी ढांचा महत्त्वाकांक्षा केवल आकांक्षा बनकर रह सकती है। सरकार ने हाल ही में तीन वर्षों के लिए 852 परियोजनाओं की पीपीपी पाइपलाइन की घोषणा की है जिनका कुल मूल्य लगभग 17 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 232 केंद्रीय परियोजनाएं लगभग 13.15 लाख करोड़ रुपये की हैं जबकि शेष 620 परियोजनाएं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अकेले लगभग 8.77 लाख करोड़ रुपये की 108 परियोजनाओं की योजना बना रहा है।

कांग्रेस भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट सरकार रही, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया: सीएम साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की उपलब्धियों और नीतियों को रखते हुए विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार स्पेशलिस्ट सरकार के रूप में काम करती रही, जबकि वर्तमान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए कई दोषियों को जेल के पीछे पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, सुरक्षा और विकास के त्रिस्तरीय संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और उन्हें विश्वास है कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पहले स्कूल जलाए जाते थे और हथियारों की फैक्ट्रियां संचालित होती थीं, वहीं आज बस्तर में स्कूल संचालित हो रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं और लोगों को बेहतर उपचार मिल रहा है। पुनर्वास नीति के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रदेश में तेजी से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। बस्तर पंडुम में इस वर्ष 54 हजार कलाकारों का पंजीयन सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रमाण है। होमस्टे योजना को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार किए जा रहे हैं।

उन्होंने नया रायपुर स्थित ट्राइबल म्यूजियम की सराहना करते हुए कहा कि वहां हजारों पर्यटक पहुंच रहे हैं और देश के मुख्य

न्यायाधीश ने भी इसकी प्रशंसा की है। श्री रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों लोगों को अयोध्या दर्शन कराया गया है, जबकि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी 5 हजार से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। चरण पादुका योजना को पुनः प्रारंभ कर तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बीते 10 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक है। किसानों से 21 क्विंटल तक 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी गई है और शेष अंतर राशि होली से पहले किसानों को दी जाएगी। सिंचाई क्षेत्र में जहां पिछली

सरकार ने 5700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, वहीं वर्तमान सरकार ने 10700 करोड़ रुपये स्वीकृत कर किसानों को मजबूत आधार देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और इसे पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए नया अधिनियम लाया जाएगा। नया रायपुर में 'अंतरिक्ष संगवारी' पहल शुरू की गई है तथा शासकीय कर्मचारियों को कैशलैस उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे क्षेत्र में 47 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'जी राम जी योजना' मनरेगा से बेहतर मॉडल है, जिसमें 100 के स्थान पर 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हाफ बिजली बिल से आगे बढ़कर मुफ्त बिजली की दिशा में जाने की है, जिसके लिए सोलर पैनल स्थापना पर सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को सुशासन, सुरक्षा और समृद्धि के नए शिखर पर पहुंचाना है। चर्चा के उपरांत सदन ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बार-बार यह आरोप लगाया जाता है कि बस्तर को कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है, लेकिन यह पूरी तरह निराधार है। हम बस्तर में सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं।

स्मृति पुस्तकालय योजना को मिल रहा जनसमर्थन 200 पुस्तकें दान कर हरीशंकर ने पेश की मिसाल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार जिले में संचालित स्मृति पुस्तकालय योजना के तहत ज्ञान दान की दिशा में जनसहभागिता लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में सृजन एकैडमी के संचालक हरीशंकर वर्मा द्वारा सीजीपीएससी, टेस्ट सीरीज, इंटरनेशनल एवं नेशनल करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट एवं कम्प्यूटर की 200 पुस्तकें जिला प्रशासन को दान कर प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने उनके इस सराहनीय योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रमाण पत्र एवं प्रेरक पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास से जरूरतमंद एवं प्रतिभावान अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा।उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 7700 से अधिक पुस्तकें दान की जा चुकी हैं। इन पुस्तकों का लाभ जिले के अनेक विद्यार्थियों को मिल रहा है। यह अभियान केवल पुस्तक दान तक सीमित नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को संवारने और उनके भविष्य निर्माण का संकल्प है।

जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बनें। पुस्तक अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दान करने हेतु इच्छुक नागरिक फोन के माध्यम से प्रभात सक्सेना 94060 49000 एवं केदार पटेल 94255 02970 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुमार बिश्वरंजन एवं जिला रोजगार अधिकारी केदार पटेल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

बजट में कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा

मुख्यमंत्री साय से कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुलाकात कर जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज यहां छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित उनके कार्यालय कक्ष में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य बजट में कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कैशलैस चिकित्सा सुविधा शामिल किए जाने पर अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री साय से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। गंभीर बीमारी की स्थिति में आर्थिक चिंता से मुक्ति मिलना एक ऐतिहासिक एवं कर्मचारी हितैषी कदम है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता है तथा आशा करता है कि भविष्य में भी कर्मचारी हितों को इसी प्रकार प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी सरकार अधिकारियों-कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। कैशलैस चिकित्सा सुविधा का लाभ शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा। मेडिकल लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण से कर्मचारीगण अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर निश्चिंत रहेंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी कार्य गुणवत्ता पर भी पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल में कमल वर्मा , सुनील उपाध्याय, जय कुमार साहू, राजेश सिंघी, संतोष कुमार वर्मा, संजीत शर्मा, देवाशीष दास, लोकेश वर्मा, अमित शर्मा, मती सोनाली तिडके, आकाश त्रिपाठी, जगेश्वर भट्ट, दीपक सोनकर मौजूद रहे।

उप मुख्यमंत्री ने केमिस्ट के पद पर चयनितों को सौंपे नियुक्ति पत्र

रायपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में केमिस्ट के पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 10 चयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक और प्रमुख अभियंता ओंकेश चंद्रवंशी भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव ने नव नियुक्त

केमिस्टों को संबोधित करते हुए कहा कि केमिस्टों की संख्या बढ़ने से विभागीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी तथा मैदानी स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। इन नियुक्तियों से विभाग में तकनीकी रूप से दक्ष मानव संसाधन की संख्या बढ़ी है। साव ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया से प्रदेश के युवाओं में विश्वास और उत्साह बढ़ा है। युवाओं को उनकी मेहनत और प्रतिभा का उचित प्रतिफल मिल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनियुक्त सभी केमिस्ट पूर्ण निष्ठा, अनुशासन और सेवा-भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा विभागीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि जल गुणवत्ता की निगरानी में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रयोगशालाओं की कार्यप्रणाली को आधुनिक एवं परिणाममुखी बनाया जाएगा।

फिल्म सिटी के लिए पेड़ काटने के विरोध में गड्ढे में उतरे कांग्रेसी

रायपुर। राजधानी के नवा रायपुर स्थित तूता इलाके में प्रस्तावित फिल्म सिटी निर्माण का विरोध अब तेज हो गया है। फिल्म सिटी के लिए करीब 1500 पेड़ों को काटे जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने आज एक बेहद अनोखा और आक्रामक प्रदर्शन किया। पर्यावरण संरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमीन पर खोदे गए गड्ढों में उतर गए और सरकार के इस फैसले के खिलाफ नारेबाजी की।

कांग्रेस का तर्क है कि नवा रायपुर को एक ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया गया है। एक साथ 1500 परिपक्व पेड़ों की कटाई से न केवल स्थानीय पर्यावरण और तापमान पर असर पड़ेगा, बल्कि यह वन्यजीवों के आवास को भी प्रभावित करेगा।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता उन स्थानों पर बने गड्ढों में उतर गए जहां निर्माण कार्य के लिए पेड़ों को हटाया जाना है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार विकास के नाम पर हरियाली का कत्ल कर रही है। तूता क्षेत्र, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहां फिल्म सिटी के नाम पर कंक्रीट का जंगल खड़ा करने की कोशिशों का विरोध स्थानीय स्तर पर भी शुरू हो गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार नवा रायपुर में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर फिल्म सिटी का निर्माण कर रही है। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि इसके लिए किसी अन्य वैकल्पिक जमीन की तलाश करने के बजाय फलते-फूलते पेड़ों को काटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि फिल्म सिटी का नक्शा बदला जाए या इसे ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पेड़ों की बलि न देनी पड़े।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

नेता प्रतिपक्ष महंत के निवास पहुंचे दिग्विजय सिंह

रायपुर। डॉ. महंत के निवास पर कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत, पुत्र सूरज महंत ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया।इस अवसर पर प्रदेश के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उपमुख्यमंत्री टी, एस सिंहदेव, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, पूर्व सांसद गंगा पोटाई, जयसिंह अग्रवाल, विधायक कवासी लखमा, उमेश पटेल, अटल श्रीवास्तव, पूर्व विधायक गुरमुख सिंह होरा, अमितेश शुक्ल, राजकमल सिंघानिया, गुलाब कमरों, यु.डी. मिंज, विनय जायसवाल, मोहित करकेट्टा, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, अनीता शर्मा, अम्बिका सिंहदेव, पीसीसी महामंत्री मालकित गैदु, वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी, दीपक दुबे, संजय पाठक, प्रमोद चौबे, प्रमोद दुबे, ज्ञानेश शर्मा, अमित पांडे, घनश्याम राजू तिवारी, अमरजीत चावला, हरीश परसाई, मनोज चौहान, शोभा यादव, हसन खान, बबिता नतथानी आदि उपस्थित थे।

माहेश्वरी महिला संगठन का रजत उत्सव नव उमंग 27-28 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन का अधिवेशन एवं रजत उत्सव 27-28 फरवरी को राजधानी रायपुर के माहेश्वरी भवन डुंडा में आयोजित है, उक्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी कविता राठी ने बताया कि अधिवेशन के प्रथम दिवस पर औद्योगिक मेले का उदघाटन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष शशि गट्टानी ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात नवनिधि रामायण पर आधारित समिति संयोजिकाओ द्वारा प्रोग्राम एवं सम्मान आयोजित है,जहां दूसरे सत्र में रजत उत्सव के तहत भूतपूर्व अध्यक्ष का सम्मान किया जाएगा जिसके पश्चात रात्रि नवरस एवं नव तंबोला प्रतियोगिता आयोजित की गई है। वही अधिवेशन के दूसरे दिवस पर प्रातः ट्रेजर हंट प्रतियोगिता आयोजित है जिसके पश्चात रंग बिरंगी होली खेली जाएगी। राठी ने बताया कि प्रथम सत्र का शुभारंभ नव परिवर्तन- शेष जिंदगी विशेष जिंदगी विषय से होगा। नव संचार एवं नव वक्ता प्रतियोगिता आयोजित है। वही अधिवेशन का समापन समाज की महिलाओं के सम्मान के साथ होगा जिन्होंने विशेष उपलब्धियों हासिल की है। इसके साथ ही पदाधिकारियों,नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष-सचिव, कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया जाएगा।

वाटर फॉर आल जिला प्रशासन की अभिनव पहल

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा वाटर फॉर आल अभियान के अंतर्गत जिले के समस्त होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में नागरिकों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने हेतु नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थलीय

निरीक्षण, स्टिकर सत्यापन एवं शपथ पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान में वाटर फॉर आल का स्टिकर प्रदर्शित हो तथा ग्राहकों को बिना किसी शुल्क के स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। नियमित निगरानी एवं सघन कार्यवाही के परिणामस्वरूप अब जिले के विभिन्न होटल एवं रेस्टॉरेंट्स में ग्राहकों को निःशुल्क शुद्ध पेयजल सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। इस पहल से आम नागरिकों को विशेष राहत मिली है तथा जनहित के इस अभियान को सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त हो रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आग्रह किया गया है कि वाटर फॉर आल अभियान की मॉनिटरिंग निरंतर जारी रहेगी तथा शिकायत या समस्या पाए जाने पर जिला कॉल सेंटर के नंबर 9977222564 पर शिकायत करें।

एनएसयूआई ने डीईओ कार्यालय का किया घेराव

रायपुर। कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आनन-फानन में जारी किए जाने के विरोध में एनएसयूआई ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रायपुर का घेराव किया। संगठन ने परीक्षा तिथियों में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को पर्याप्त तैयारी का समय दिया जाना चाहिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने 23 फरवरी को परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए संबंधित स्कूलों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगे।घेराव का नेतृत्व कर रहे अनुज शुक्ला और हेमंत पाल ने आरोप लगाया कि पीएम श्री विद्यालयों की जांच के लिए दिल्ली से टीम के संभावित दौरे को देखते हुए विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल्दबाजी में परीक्षा तिथि तय की गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हड़बड़ी से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

समावेशी मुस्तकबिल का मुतवाज़िन बजट: अली

रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी द्वारा माली साल 2026-27 के लिए पेश 1.72 लाख करोड़ रुपए के बजट को भारतीय जनता पार्टी, जिला रायपुर के जिला उपाध्यक्ष अकबर अली ने अवाम की तरक़्क़ी, समाजी इंसाफ और मुस्तकबिल की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया मुतवाज़िन और दूरअंदेश बजट क़रार दिया है। अकबर अली ने कहा कि वज़ीर-ए-आला विष्णु देव साय की क़ियादत और वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी की पेशकश में यह

बजट वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और विकसित भारत के ख़्वाब को ज़मीन पर उतारने वाला मज़बूत दस्तावेज़ है। इसमें ग़रीब, किसान, नौजवान, ख़्वातीन, मज़दूर और आदिवासी तबक़ात- हर तबके के हितों का ख़ास ख़्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में रायपुर में 200 बिस्तरों के नए अस्पताल, मातृ-शिशु अस्पतालों की तामीर, 25 डायलिसिस सेंटर, 50 जन औषधि केंद्र और मेकाहारा रायपुर में एआई आधारित जदीद इलाज़ी सहूलतों का इंतज़ाम अवाम को सस्ती, आसान और बेहतर सेहत सेवाएं देने की अहम पहल है। 4 नए मेडिकल कॉलेज और 1 होम्योपैथिक कॉलेज क़ायम होने से तिब्बी तालीम और रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा होंगे।

हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भविष्य की योजनाओं पर अर्धदिवसीय सेमिनार आयोजित

ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद : डॉ. यादव

रायपुर। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा आज छत्तीसगढ़ को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्लोबल क्लीन एनर्जी के विस्तार के उद्देश्य से अर्धदिवसीय सेमिनार का आयोजन कोर्टयार्ड बाय मैरियट में किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग के सचिव रोहित यादव (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

सचिव रोहित यादव ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक परिवेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना तथा पारंपरिक औद्योगिक ईंधनों के स्थान पर स्वच्छ विकल्पों को अपनाने की दिशा में कार्य करना है। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे जैविक खेती को बढ़ावा

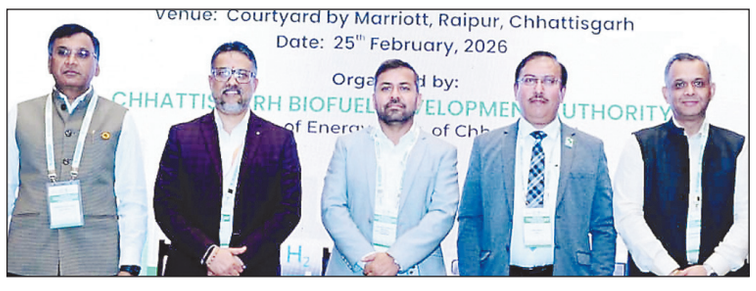

मिलने के साथ किसानों की आय में भी वृद्धि हो सकेगी।

सेमिनार में चर्चा के दौरान बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कृषि अवशेष, डेयरी उद्योग से उत्पन्न अपशिष्ट, फल एवं सब्जी मंडियों का जैविक कचरा तथा गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उपयुक्त तकनीक के माध्यम से इनके प्रसंस्करण द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं।राज्य में स्टील एवं स्पंज आयरन उद्योग का मजबूत आधार रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्र जैसे उरला, सिलतरा, भिलाई तथा रायगढ़ के औद्योगिक क्षेत्रों में है। इसके अतिरिक्त जगदलपुर एवं बस्तर में भी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।

ग्रीन हाइड्रोजन को औद्योगिक ईंधन के रूप में अपनाने से दोहरे लाभ होंगे–एक ओर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं बायोमास के मूल्य संवर्धन से किसानों की आय में वृद्धि होगी। यह पहल भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अपशिष्ट से आय सृजन तथा नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी।

ऊर्जा विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने कहा कि सेमिनार का उद्देश्य राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम में ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग को बढ़ावा देना, भविष्य के अनुसंधान की दिशा तय करना, संभावित बाधाओं की पहचान करना तथा इसके व्यापक क्रियान्वयन के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।सेमिनार में उपस्थित विशेषज्ञों ने भी अपने विचार साझा किए।

बीरगांव मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान

रायपुर। राजधानी के उत्तर जोन में यातायात व्यवस्था को सुचारु और सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस एवं नगर निगम की संयुक्त टीम ने आज बीरगांव नगर निगम मुख्य मार्ग पर अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया। यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त मयंक गुर्जर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा, सहायक पुलिस आयुक्त रमेश येरेवार, थाना उरला पुलिस बल तथा नगर निगम बीरगांव के अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई। अभियान के दौरान मुख्य मार्ग और फुटपाथ के किनारे अनाधिकृत रूप से संचालित दुकानों, ठेलों, गुमटियों और अन्य अस्थायी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि कई स्थानों पर सड़क और पैदल मार्ग पर अवैध कब्जे के कारण आम नागरिकों एवं वाहन चालकों को आवागमन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अतिक्रमण की वजह से यातायात बाधित हो रहा था और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही थी।

संयुक्त टीम ने व्यवस्थित तरीके से कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे फैले अवैध ढांचे और अवरोधों को हटाया। विशेष बात यह रही कि पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से की गई, जिसमें आवश्यकतानुसार समझाइश और संवाद को प्राथमिकता दी गई। संबंधित संचालकों को मौके पर ही चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न करें तथा केवल निर्धारित स्थानों पर ही अपना व्यवसाय संचालित करें। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.